fo"k; lwph | lEikndh; | कमल संदेश


**नव भाजपा अध्यक्ष**

रिपोर्ट................................ 4
एक परिचय.................... 9
पहली प्रेस कांफ्रेंस........... 11
लेख : परिवर्तन की बयार
çHkkr >k.................. 7




डा. मुरली मनोहर जोशी... 13
यशवन्त सिन्हा.................. 14
एम. वेंकैया नायडू............ 16
अरुण जेटली.................... 18

**लेख**

महंगी पड़ती संप्रग सरकार
jktho i rki :Mh...... 20
नीतियों की भूल–भुलैया
Mk- ejyh eukgj tk'kh. 22
एक और हजार का फर्क
Mk- on i rki ofnd.. 26
आरक्षण की धूर्त बिल्ली
fQjkst c[r vgen.... 29

**प्रदेशों से**

दिल्ली................................ 24
मध्यप्रदेश, कर्नाटक........... 25



**सम्पादक**
çHkkr >k] lkln

**सम्पादक मंडल**
lR; iky
d- d- 'kek
lto dekj flUgk

**पृष्ठ संयोजन**
/keUæ dk'ky

**सम्पर्क**
Mk- edth Lefr U;kl
ih-ih&66] lcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qku u- +91¼11½&23381428
QDl ¼ +91¼11½&23387887
lnL;rk grq ¼ +91¼11½&23005700

**सदस्यता शुल्क**
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

***e-mail address***
**kamalsandesh@yahoo.co.in**

**प्रकाशक एवं मुद्रक :** डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा


*पापकर्मों का क्षय हो जाने पर ही पुरुष को ज्ञान होता है।*
**-महा. शान्ति.** 204@8

# झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम

# देखें, जांचें, परखें

Vk शा थी कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार नहीं बनी तो कम से कम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी ही। पर न सत्ता में आ पाए और न बड़ी पार्टी बन सके। खासकर चुनाव में परिणामों को लेकर अनुमान ही लगाया जा सकता है और आंकलन किया जा सकता है। आंकलन भी सही नहीं और अनुमान भी अनुकूल नहीं। कारणों की तलाश तो समीक्षा बैठकों में होगी पर फौरी तौर पर देखने में आता है कि अब हम कार्यकर्ताओं पर कम और सर्वे कंपनियों पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। हम शायद भूल जाते हैं कि कार्यकर्ताओं का संबंध संगठन की आत्मा से होता है और सर्वेरियर का संबंध अपने व्यवसाय से होता है। हम अक्सर कहते हैं कि राजनीति मिशन है व्यवसाय नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मिशन में कार्यकर्ताओं से ज्यादा संबंध बनाए और व्यावसायिक सूचनाओं पर कम निर्भर रहें।

बाजार का गिरना और उछलना यह सेंसेक्स का ग्राफ तो हो सकता है पर राजनीति का नहीं। राजनीति में तो जन के मन को समझना होता है और मन को दूर से नहीं पास जाकर समझा जा सकता है। सतत् प्रवास ही एकमात्र उपाय है। जब प्रवास होगा तो संवाद होगा। संवाद होगा तो कुशलता का आदान–प्रदान होगा। वातावरण में क्या घट रहा है इसको समझने में आसानी होगी। कहीं न कहीं निरंतर और अनथक प्रवास में कमी आई है। हम अपने दल की तुलना यह कहकर तो नहीं कर सकते कि क्या ऐसा कांग्रेस में होता है। भाजपा, भाजपा है। वह कभी कांग्रेस नहीं हो सकती। जनता उसे भाजपा के रूप में ही देखना चाहती है। प्रवास से प्रवाह की गति पहचानी जा सकती है। प्रवास करने वाले कार्यकर्ताओं की टीम बढ़ानी होगी। मिशनयुक्त जीवन को कार्य में जुटाना होगा।

राजनीतिक संगठनों में समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी उसे देना चाहिए जो संगठन में कम से कम समस्या न बना हो। होता यह है कि जो बड़े स्थानों पर समस्या हैं वे छोटे स्थानों पर समाधान करने चले आते हैं। सूचना क्रांति की इस दौर में जनता और कार्यकर्ताओं से कुछ भी छुपा नहीं रहता। समाधानकर्ता नैतिकवान हो, श्रद्धावान हो, उसकी छवि निर्णय लेने या देने की हो तो शायद वह संगठन के साथ न्याय कर पाएगा।

लोकसभा चुनाव एवं इसके बाद हुए झारखंड सहित चार विधानसभा चुनावों में सफलता न मिलने के कारण यह तो आवश्यक सा लगता है कि हमें अपने दल में चयन प्रक्रियाओं, चुनावी क्रियाओं सहित चुनाव से जुड़े सभी कार्यों पर गहराई से विचार करना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में वो सारी अनुकूलताएं थीं जो एक विपक्षी दल को सत्ता में आने के लिए आवश्यक लगती; बेलगाम महंगाई, चरम भ्रष्टाचार, कांग्रेस की असफलता, केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा लिए जाने वाले गलत फैसले के बाद भी परिणाम का प्रतिकूल आना हमें आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करता है।

समय आ गया है जब हम अपने को, अपनी आंखों से कम सबकी आंखों से अधिक देखें। देखने के बाद जो सच दिखे, उसमें जो दूर करने वाली बात हो उसे दूर करें और उसमें जो ग्राह्य करने वाली बात हो उसे ग्राह्य करें। तो शायद हम जन–गण–मन के अनुकूल अपने को ला पाएंगे। हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम 'कुछ भी नहीं' की श्रेणी में आ खड़े होते हैं तो लोग दोष औरों को नहीं हमें ही देंगे। हम अधिक से अधिक दोषरहित बनें तब जाकर लोग हमारे गुणों की ओर देखना शुरू करेंगे। जब लोग हमारे गुणों की ओर देखेंगे तो जन–जन में हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी और जैसा परिणाम हम चाहते हैं वैसा ही मिलेगा।

# नितिन गडकरी बने भाजपा के नए अध्यक्ष

गत 19 दिसम्बर को भाजपा के संसदीय दल की बैठक के बाद 52 वर्षीय श्री नितिन गडकरी को पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं श्री आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने गडकरी को बधाई दी।

**सभी को साथ लेकर चलेंगे**

अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री गडकरी ने पार्टी नेताओं को भरोसा दिलाया कि वह पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने सभी से मार्गदर्शन देने की अपील की और कहा कि नई जिम्मेदारी को लेकर काफी खुश और उत्सुक हैं।

उन्होंने कहा कि वे विकास की राजनीति करेंगे। गडकरी ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों की नई समिति बनने में फिलहाल कुछ समय लगेगा अतः वे सभी उनको पहले की भांति सहयोग देते रहें। पद सम्भालने के बाद श्री गडकरी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके निवास गए।

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वे अगले तीन साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी का काम देखना सर्वोपरि रहेगा। वे केन्द्रीय राजनीति के लिए नए है और पार्टी ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिसे वे आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में पूरी करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष पद संभालने के बाद वे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री वैकेंया नायडू भी मौजूद थे। आडवाणी जी से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

इसके बाद श्री गडकरी नागपुर पहुंचे। नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष के स्वागत में पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। हवाईअड्डे से लेकर उनके घर तक लोगों की भारी भीड़ नजर आई। संघ का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने नागपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

**भाजपा में परिवारवाद नहीं**

इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्हें चार साल में कई खट्टे–मीठे अनुभव हुए। कार्यकाल के दौरान सभी का सहयोग मिला, लेकिन प्रमोद महाजन की कमी खली। उन्होंने कहा कि भाजपा में परिवारवाद को कोई जगह नहीं है। पार्टी में छोटा कार्यकर्ता भी ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है।

इस मौके पर श्री आडवाणी ने कहा कि गडकरी को पार्टी के सभी नेताओं, पदाधिकारियों, संसदीय बोर्ड और उनका आशीर्वाद प्राप्त है। लोग गडकरी को उनके काम की बदौलत जानते हैं और उनकी लोकप्रियता सर्वविदित है।

**छात्र नेता से अध्यक्ष तक**

- मई 1957 में जन्म
- एबीवीपी के माध्यम से छात्र राजनीति में, विदर्भ इकाई के अध्यक्ष बने
- गत 20 साल से लगातार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य
- 1995–99 में भाजपा–शिवसेना गठबन्धन सरकार में सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री
- इस दौरान मुम्बई तथा पुणे के बीच एक्सप्रेस हाइवे बना
- महाराष्ट्र सरकार में निजीकरण उच्चाधिकार समिति के सदस्य
- महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन विकास निगम के अध्यक्ष रहे
- 1999 से 2005 तक वह महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। ■

# नितिन गडकरी ने लिए 'बड़ों' से आशीर्वाद

पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति पूरी विनम्रता व सदाशयता का परिचय देते हुए नए भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी सबसे पहले श्री राजनाथ सिंह से गले मिले। उसके

बाद उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी के पैर छू कर उनका आशीर्वाद लिया। बाद में वे मंच की बांई ओर लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज की ओर मुड़े और उनके पैर छू कर उनसे आशीर्वाद लिया।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू भी मंच पर आए और उन्होंने माला पहना कर गडकरी का अभिवादन किया। वैसे सबसे पहले श्री राजनाथ सिंह ने माला पहना कर गडकरी का स्वागत किया। उसके बाद श्री आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज ने गडकरी को माला पहना कर अभिवादन किया।

भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और पदाधिकारियों को यकीन दिलाया है कि वह नीचे से ऊपर तक सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त कर पार्टी को नई ऊंचाईयों तक ले जाएंगे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से स्वीकारा कि राष्ट्रीय राजनीति का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि वह ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जिससे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किसी भी तरह गर्दन झुकानी पड़े। उन्होंने राष्ट्रवाद के रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए कहा कि वे सभी का सहयोग लेंगे और हर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं व नताओं का स्नेह पाकर आगे बढ़ने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे।

**मौजूदा पदाधिकारी पदों पर बने रहेंगे**

श्री नितिन गडकरी ने अपने निर्वाचन के साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि पार्टी के वर्तमान पदाधिकारी पार्टी संगठन के विधिवत गठन तक अपने–अपने पदों पर बनें रहेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का स्वरूप तय करने में अभी वक्त लगेगा, ऐसी दशा में सभी पदाधिकारी पार्टी को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं। इस तरह की भी अटकलें लगाई जा रही थी कि गडकरी के पास पहले से तय टीम होगी, जो पार्टी के पुराने पदाधिकारियों को हटा कर संगठन को अपने हाथ में ले लेगी।

**पार्टी मुख्यालय में दिवाली**

अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय में 24 घंटे बाद यह दूसरा मौका था जब सुबह से ही भारी गहमागहमी रही। नए अध्यक्ष की ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए दिल्ली भाजपा इकाई की ओर से बाकायदा ढोल–नगाड़े और जबरदस्त आतिशबाजी की गई। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी भाजपा मुख्यालय में उपस्थित थे। ■

## गडकरी ने लिया आडवाणीजी का आशीर्वाद

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 20 दिसम्बर को पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और अपने कार्यकाल के लिए उनसे आशीर्वाद एवं सहयोग मांगा।

श्री गडकरी ने श्री आडवाणी और उनके परिजनों से मुलाकात की। सुबह के नाश्ते के अवसर पर हुई इस मुलाकात में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम वेंकैया नायडू भी उपस्थित थे।

श्री गडकरी ने कहा, मैं दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में नया हूं लेकिन वरिष्ठ नेताओं से आशीर्वाद मिलने के बाद में मैं मुझे दी गई जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने के प्रति आश्वस्त हूं।

भाजपा अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद श्री गडकरी ने श्री वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह एवं श्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की थी। ■

# लोकसभा एवं राज्यसभा में भाजपा संसदीय दल की नव नियुक्तियां

गत 21 दिसम्बर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता पद पर श्री गोपीनाथ मुण्डे तथा मुख्य सचेतक के पद पर श्री रमेश बैस की नियुक्ति की है। उन्होंने राज्य सभा में भाजपा संसदीय दल के उपनेता पद पर श्री एस.एस. अहलूवालिया

और मुख्य सचेतक पद पर श्रीमती माया सिंह की भी नियुक्ति की है। वह पहले ही लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली की घोषणा कर चुके हैं। श्री आडवाणी ने इन सभी नियुक्तियों की सूचना लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभा के माननीय सभापति को भेज दी हैं।

**भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव**

19 दिसम्बर को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बात की सराहना एवं आभार प्रगट किया गया कि श्री राजनाथ सिंह ने अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान पार्टी का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया। श्री राजनाथ सिंह ने पार्टी का नेतृत्व एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण काल में किया। उन्होंने पार्टी के वैचारिक एवं संगठनात्मक हितों के प्रति पूर्णतः स्वयं को समर्पित बनाए रखा। भाजपा संसदीय बोर्ड उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है और विश्वास करता है कि पार्टी को उनकी सेवाएं पूर्णतः उपलब्ध रहेंगी।

## मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरु : आडवाणी

गत 18 दिसम्बर को पूर्व उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का श्रेय आरएसएस को देते हुए कहा कि यदि वह प्रचारक न बने होते तो शायद उनकी यह यात्रा भी शुरू न होती।

भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के प्रति आभार जताते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता पद से मुक्त होने के बाद वह राहत महसूस कर रहे हैं। एक समाचारपत्र में 'रथयात्री रथ से उतर गया है' इस शीर्षक से छपे समाचार का हवाला देते हुए श्री आडवाणी ने कहा, वास्तव में मेरी रथयात्रा आयु के 14वें वर्ष से शुरू हुई जब वे संघ के स्वयंसेवक बने थे। तब से यह रथयात्रा जारी है और आगे भी जारी रहेगी। अतः इससे उतरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस यात्रा में स्वयंसेवक व प्रचारक, बाद में राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद संसदीय जीवन की यात्रा की। उन्होंने कहा, भाजपा कार्यकर्ता अपना निजी एजेंडा छोड़ कर कार्य करेंगे तो देश की समृद्धि, प्रगति और विकास के लिए जनता की अपेक्षा के अनुरूप स्वयं को सक्षम साबित कर सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष की नेता मनोनीत होने पर श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि छोटे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है। इसे स्वीकार करने से पूर्व उन्होंने कहा था कि आडवाणी संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में मार्गदर्शन हेतु उनके साथ होंगे तो वह यह जिम्मेदारी निभा पाएंगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद पर मनोनीत श्री अरुण जेटली ने कहा कि आडवाणीजी के मार्गदर्शन में भाजपा संसद में आम मुद्दों को लेकर आम व्यक्ति की लड़ाई लडेगी। भाजपा अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी जी का कद किसी पद का मोहताज नहीं। भाजपा कार्यकर्ता उनका सम्मान पद के कारण नहीं बल्कि विचारधारा और संगठन के प्रति उनके समर्पण भाव के कारण करते हैं और यह सम्मान हमेशा बना रहेगा। ■

# परिवर्तन की सुखद बयार

**& çHkkr >k**

tk जब होना होता है वह तभी ही होता है। हुआ भी यही। परिवर्तन! परिवर्तन!! परिवर्तन!!! अरसे बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक ने कहा था, 'विचार सनातन है और युगानुकूल परिवर्तन अवश्यंभावी है।' सच तो यही है जो आज है वह कल नहीं, जो अभी है वह कभी नहीं। कल की आस आज को जीवित रखता है और आज की आस भविष्य को निमंत्रित करता है। हम नेवैद्य और प्रसाद बनकर जीने वाले लोग है। हम निमित्त है, नियति नहीं। हम परिवार में रहते है इसलिए संसार के बारे में सोचते है। हम संसार को परिवार की इकाई मानते हैं। परिवार की सुदृढ़ता में संसार की सुदृढ़ता है। परिवार, समाज, संगठन, संस्था और देश का राज–काज जब अच्छा चल रहा हो तब समझना चाहिए कि यहां सामंजस्य है, समन्वय है, सद्भाव है, सामूहिकता है और आपसी विश्वास के साथ–साथ सदाशयता की सरिता भी बह रही है। ये सभी बातें आज भाजपा की महती आवश्यकता है।

18 दिसम्बर की शाम। लोकसभा की एनेक्सी में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में 56 वर्ष बाद एक परिवर्तन होते देखा गया। न वो सत्ता का हस्तांतरण था न व्यक्तियों का, बल्कि वहां पर विश्वास से उपजी व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा था। सब खुश थे दीर्घा में बैठे संसदगण इतिहास को घटते स्वयं देख रहे थे और वे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे थे। घटते इतिहास का साक्षी बनना। सौभाग्य की बात है। सन् सत्तावन से लेकर अब तक जनसंघ या भाजपा के संसदीय दल के नेता या तो अटलजी रहे या आडवाणी जी। विश्वास की अटूट कड़ी को प्रणाम। आपसी समझ को नमन। सहचर को दंडवत्। आपसी पूरकता को आदरांजलि। दोनों के बीच अद्भुत संगम। बेमिसाल जोड़ी। जो लाखों परिवारों की विचारधारा से जोड़ा। एक ने कहा दूसरे ने माना, दूसरे ने कहा, सबने माना। कहीं नहीं आनाकाना। मतभेद पर बहस। मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं। बहस तब तक जब तक कोई निर्णय नहीं। निर्णय के बाद निर्णय को सिर्फ निर्णायक स्थिति तक पहुंचाना। ऐसी अनेक बातें उनसे समझने और सीखने की है। सीखने–समझने के लिए करीब रहना ही पड़ता है।

19 दिसम्बर, 2009 को भी भाजपा के केन्द्रीय कार्यालय के हाल में इतिहास घट रहा था। 52 वर्षीय नितिन गडकरी, आडवाणी जी, राजनाथ जी, सुषमाजी और अरूण जेटली जी के मध्य ''होनहार बिरबान के होत चिकने पात'' की तरह बैठे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वे उन चारों से आशीष ले रहे हैं और भाजपा के माध्यम से भारत माता को परमवैभव पर ले जाने का संकल्प ले रहे हों। 18 और 19 दिसम्बर, 2009 को नवविहान में नवसंदेश, नवसंकेत और नवरचना का नव इतिहास लिखने की तैयारी सी लग रही थी। युद्ध सेनापति की अगुवाई में सैनिक लड़ते हैं। यह सर्वविदित है पर यह भी सर्वविदित है कि सेनापति बनने से पहले सैनिक की भूमिका, सेनानियों के बीच काम लेने की भूमिका और अपने संकेतों पर उनके मर मिटने की प्रेरणा भरना, दैवीय शक्ति भी उनमें जागृत करना पड़ता है। नितिन जी को अपने संकेतों को समझाने के लिए, अपने सिद्धांतों को मनवाने के लिए, अपने संकेतों पर युद्ध में झोंकने के लिए, अपने सैनिकों के बीच प्रेरणास्पद भाव जागृत करने का क्रम चलाना होगा। यह क्षमता उनमें है। जिस तरह पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दायित्वमुक्त होते ही अपनी कुर्सी पर श्री नितिन गडकरी को दायित्वयुक्त कर तत्काल बैठाया उसे देख हर कोई कहेगा कि यह भाजपा जैसे संगठन में ही संभव है। जिस नींव में निर्माण की क्षमता नहीं होती है उस नींव के बीज को बांझ कहने में लोग संकोच नहीं करते। भाजपा की नींव में निर्माण की अपार शक्ति है। संभावनाओं से भरे एक नहीं अनेक लोगों की तलाश की जा सकती है। और जब तलाशने का काम होगा तभी उन्हें तराशा जाएगा। इसलिए सदैव तलाश जारी रहनी चाहिए और तराशने का क्रम भी चलते रहना चाहिए। ऐसा होते रहने पर संगठन संस्कारों से संपन्न रहता है और निर्माण का क्रम अनवरत् चलता रहता है।

***18 और 19 दिसम्बर, 2009 को नवविहान में नवसंदेश, नवसंकेत और नवरचना का नव इतिहास लिखने की तैयारी सी लग रही थी।***

यह राजनीतिक क्षेत्र है। यहां विचार और व्यवहार में संतुलन परमावश्यक है। विचार की प्रबलता के साथ–साथ व्यवहार की सबलता से कार्य की संपन्नता सहजता से हो जाती है। संगठन की सबलता से सिर्फ चुनाव नहीं, जन का मन भी जीता जाता है। आज हो यह रहा

है कि लोग चुनाव जीतते हैं, जन का मन नहीं। धीरे–धीरे धारणा यह भी होती जा रही है कि चुनाव संगठन नहीं पैसा जीतता है। लोग कहने तो यहां तक लगे हैं बाकी सब प्रत्याशी करता है। यह भाव बदलना होगा। संगठन है सर्वोपरि तो करनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए वह संगठन की कुशलता में हाथ बंटाएं। क्योंकि सबल सगंठन से सरकार लाई जाती है। पर सरकार से संगठन का निर्माण नहीं होता। हां यह जरूर है सुशासन से संगठन सुगठित होता है।

***नेतृत्व और कार्यकर्ता में नैसर्गिक संबंध रहना चाहिए। नाभि–सेतु–संबंध रहना चाहिए। प्रतिबद्धता नैतिक बंधन से जुड़ी होनी चाहिए। संगठन में कसावट की सजावट अच्छी लगती है। स्व–अनुशासन का जागरण स्वतः कैसे हो, विचार तो इस पर भी होना चाहिए। मुक्त मंथन को उन्मुक्त मौसम चाहिए।***

कोई नहीं उड़नपरी। हम धरती के लोग हैं धरती हमारी जीविका है। धरातल हमारा आधार है। हमें धरती की लड़ाई लड़नी है। जब हम धरती कहते हैं तो हमें संघर्ष के लिए धरा का एक बड़ा आधार मिलता है। हमने धरती को मां माना है। और मां की आन–बान शान के लिए धरापुत्र होने के नाते धरती की लड़ाई लड़ना हमारा परम कर्त्तव्य है। हम लड़ेंगे। मिलकर लड़ेंगे। जहां एकल गीत की आवश्यकता है वहां एकल गीत गायेंगे लेकिन सामूहिकता को नहीं भूलेंगे और जहां सामूहिक गीत की आवश्यकता होगी उसे गाते हुए वहां एकल गीत को नहीं भूलेंगे। नेतृत्व और कार्यकर्ता में नैसर्गिक संबंध रहना चाहिए। नाभि–सेतु–संबंध रहना चाहिए। प्रतिबद्धता नैतिक बंधन से जुड़ी होनी चाहिए। संगठन में कसावट की सजावट अच्छी लगती है। स्व–अनुशासन का जागरण स्वतः कैसे हो, विचार तो इस पर भी होना चाहिए। मुक्त मंथन को उन्मुक्त मौसम चाहिए। उन्मुक्त का अर्थ उच्छृंखलता नहीं होना चाहिए। सरलता, सादगी बाट जोह रही है। नौटंकियों का दौर समाप्त होना चाहिए। समाज आज भी सज्जनता के प्रति सदैव सद्भावना रखती है। अतः आवश्यक यह है कि सभी दिशाओं में विस्तार हो। विस्तार का आधार हो। आधार सुदृढ़ हो। ऐसा होगा तो संगठनात्मक इमारत की हर मंजिल नवलय, नवगति से निरंतर अबाध गति से बढ़ती रहेगी। सरकार आये तो संगठन को उसकी कुशलता की कामना राजनीति में होना, राजनीतिक समझ का होना दोनों में बहुत अंतर है। इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि राजनीति में बहुत लोग काम करते हैं पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि कम लोगों में राजनीतिक समझ होती है। आज की महती आवश्कता है कार्यकर्ताओं में समझ बढ़े क्योंकि समझ न होने के कारण ही अनेक नासमझियां हो जाती है। सब कुछ अच्छा होगा, की सद्भावना के साथ नवप्रभात का स्वागत है।

भारतीय संसद सुषमा जी और अरूण जेटली जी की संसदीय समझ पर नाज रखता है। दोनों संसद के गौरव है। प्रतिभा के धनी है। योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति योग्य समय पर आये हैं। ऐसा सभी ओर चर्चा है। कमल कुहलाए नहीं वह खिलता रहे। इसकी जिम्मेदारी नितिनजी के कंधों पर दी गयी है। कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देश में भाजपा का स्थान है। इस दल का अध्यक्ष बनना सामान्य घटना नहीं है। दल का अटूट विश्वास जिसके पीछे खड़ा हो उसके कदम कभी लड़खड़ा नहीं सकते। अतः जैसाकि नितिनजी ने स्वयं कहा, वो सबको साथ लेकर बड़ों का आशीष और छोटों का प्यार प्राप्त करेंगे। इससे यह प्रतीत होता है वे दल के मर्म को समझ गये हैं। नब्ज पकड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। वे सही वैद्य बनकर उभरे। देखें, जांचे, परखे। सफलता उनके कदम चूमेगी। ■

***(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद हैं)***

***गुजरात***

## निकाय चुनावों में मतदान अनिवार्य

निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान तथा महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण का विधेयक सदन में पारित कराकर मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। ऐसा करके श्री मोदी ने धनबल तथा बाहुबल से चुनाव जीतने पर अंकुश लगा दिया वहीं महिला वोट बैंक को और मजबूत कर लिया है। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस जहां अनिवार्य मतदान को लोकतंत्र विरोधी बता रही है। गुजरात के शहरी विकास मंत्री नितिन पटेल ने विधानसभा में गुजरात स्थानीय सत्तामंडल कानून (सुधार विधेयक 2009) पेश किया। जिसके बाद ऑस्ट्रिया, ब्राजील सरीखे देशों की तरह अब गुजरात में भी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करना होगा। उचित कारण बिना मतदान नहीं करने वाले नागरिकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जबकि पटेल ने गुजरात पंचायत अधिनियम (सुधार विधेयक) को महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर बताया है। अनिवार्य मतदान विधेयक के संबंध में खुद मुख्यमंत्री मोदी कहते हैं कि चुनाव में महज 25 प्रतिशत वोट पाकर राजनीतिक दल सत्ता पर आसीन हो जाते हैं। मुंबई हमले के दौरान लोगों की नाराजगी को ताजा उदाहरण बताते हुए श्री मोदी कहते हैं कि हमले के दौरान लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वह आम चुनाव में कहीं नजर नहीं आई। श्री मोदी इसे ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स बताते हैं और कहते हैं कि निरर्थक चर्चाओं के बदले लोकशाही के प्रति सजग होना चाहिए। ■

# नितिन गडकरी : एक परिचय

- अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र (नवम्बर 2004 से)
- प्रतिपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद (1999–2005)
- लोक निर्माण कार्यमंत्री, महाराष्ट्र (1995–1999)
- जन्मः 27 मई 1957, नागपुर, भारत
- शैक्षिक योग्यताः एम कॉम, एलएलबी, डीबीएम
- 1989 में ग्रेज्युएट निर्वाचन क्षेत्र नागपुर क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए निर्वाचित। 1990, 1996, 2002 (निर्विरोध), 2008 में पुनः निर्वाचित।
- महाराष्ट्र के लोकनिर्माण कार्य मंत्री– 27 मई 1995
- सदस्य, निजीकरण की उच्च अधिकार प्राप्त समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (1995–99)
- नागपुर जिला के गार्डियन मंत्री (1995–99)
- चेयरमैन, खनन नीति कार्यान्वयन समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, महानगर (मेट्रोपालिस) सौन्दर्यीकरण समिति, महाराष्ट्र सरकार (1995–99)
- चेयरमैन, राष्ट्रीय ग्रामीण सडक विकास समिति और चेयरमैन, सीपीडब्ल्यूडी समीक्षा समिति, भारत सरकार
- विदेश यात्रा– इस्रायल, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यू.के., स्विट्जरलैण्ड, जापान, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्राजील और श्रीलंका– विभिन्न शिष्टमंडलों के सदस्य रूप में।
- श्री गडकरी ने औद्योगिक तथा वाणिज्यिक विकास के माध्यम से दलितों के पुनरूद्धार के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए विकास कार्य में लगे रहे।
- श्री गडकरी ने विकास की कोरी बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी उद्यमशील कुशलता का प्रदर्शन किया। वे एक सेवानिष्ठ किसान (कृषिविद्) हैं, जिनकी सदैव जल प्रबंधन, सौर–उर्जा परियोजना और कृषि की आधुनिक तकनीकों में रूचि रही है, जिससे वे आज एक सफल चीनी फैक्टरी के चेयरमैन हैं।
- श्री गडकरी खेलों के प्रति उत्साही रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से क्रिकेट में रूचि रही है।
- कंचन के साथ विवाह, दो पुत्र– निखिल और सारंग– एवं पुत्री केटकी।
- श्री गडकरी कभी भी क्षुद्र राजनीति में नहीं फंसे। उनके लिए विकास और प्रगति ही परम उद्देश्य रहा। दलितों का उद्धार मिशन रहा। 50वें जन्मदिवस पर लोगों ने जितनी स्नेह वर्षा से उन्हें अभिसिंचित किया, वह अभूतपूर्व थी। नागपुर का लोकप्रिय सामाजिक स्थल चिटनिस पार्क उनके प्रशंसकों से भरा पड़ा था जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों के वे गरीब लोग थे जो स्वयं अपना पैसा खर्च कर वहां पहुंचे थे। एक सर्वदलीय समिति ने इस समारोह का आयोजन किया था जो नागपुर की एक अपूर्व ऐतिहासिक यादगार बन गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री गडकरी को विदर्भ भूषण और नागभूषण से सम्मानित किया गया, जिन क्षेत्रों में वे अत्यंत सम्मानीय रहे हैं।
- 1995 में लोक निर्माण कार्य विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) का मंत्री पद संभालते ही उन्होंने इस विभाग की शक्ल–सूरत बदलनी शुरू कर दी थी। उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे अपने विभाग के इंजीनियरों पर पूरा भरोसा है, जिससे इंजीनियरों में परिश्रम करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने इतने आश्चर्यजनक परिणाम देकर दिखाए जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे।
- श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में 13736 गांवों को 'हर मौसम में जोड़ने वाली सड़कों' का निर्माण कार्य किया। उन्होंने देखा कि ये सड़कें स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी जोड़ी नहीं गई थीं। उन्होंने यह भी देखा कि अगर वार्षिक बजटों पर ही इनका निर्माण होगा तो शायद 350 वर्षों में भी इनका निर्माण पूरा न हो पाए। क्योंकि सरकारी खजाने से धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने 'नाबार्ड' के अधिकारियों को समझाया और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए उदार शर्तों पर 700 करोड़ रूपए का ऋण जुटाया। साथ ही साथ, उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजीकरण को भी साथ लिया, जिससे भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का नया रास्ता खुला। बहुत ही परियाजनाएं निजीकरण के माध्यम से ली गई। 4 वर्षों के अंदर ही पर्याप्त धन उपलब्ध करके लगभग 98 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के लिए 'राउण्ड–दि–ईयर रोड कनेक्टिविटी' अर्थात् पूरे वर्षभर सड़क योजना को पूर्ण कर दिखाया। इस सफतला से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ध्यान आकृष्ट हुआ और उन्होंने उन्हें एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर उनसे भारत के लिए भी इसी प्रकार की योजना तैयार करने को कहा।
- श्री गडकरी नक्सलवादी क्षेत्रों में भी पहुंचे जहां नक्सलवादी सड़क निर्माण करने नहीं देते थे। उन्होंने सीमा सड़क संगठन (बीआओ) की सहायता ली ताकि वहां सड़कें और पुल बनाए जा सकें और इस प्रकार आदिवासियों को सहज और स्थायी सड़कों पर चलने की सुविधा मिल सके।
- श्री गडकरी ने अमरावती जिले की मेलघाट–घरनी पट्टी में आदिवासियों के कुपोषण की समस्या को हल करने के

लिए सड़कों के निर्माण के लिए एक अनूठे समाधान का प्रयोग किया। सड़कों की पहुंच न होने से आदिवासियों को चिकित्सा सहायता, राशन और शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। श्री गडकरी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस पट्टी के दूरदराज के 91 गांवों के लिए हर मौसम में काम वाली सड़कों को जोड़ा। इस क्नेक्टिविटी से इस पट्टी की सामाजिक– आर्थिक हालत ही बदल कर रख दी और कुपोषण की घटनाओं को कम करने पर नाटकीय रूप से प्रभाव पड़ा।

- श्री गडकरी को 'मुम्बई भूषण' (प्राइड आफ मुम्बई) एवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने मुम्बई में यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए कई फ्लाई ओवर पुलों, अनेक सड़कों का विस्तार, भूमिगत पथों और रेल पुलों को निर्माण कर पूरे महानगर की शक्ल ही बदल कर रख दी थी। उन्होंने ही भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बहुमंजिली पार्किंग स्थलों की कल्पना की थी। वर्ली बांद्रा सी–लिंक परियोजनाओं के जन्मदाता भी वही थे। लव ग्रोव जंकशन और महिम जैसे जोड़ने वाले प्रमुख फ्लाई–ओवर पुल भी गडकरी के जमाने में ही लगभग पूरे होने वाले थे। एप्रोच सड़कों के कंक्रीटीकरण का काम भी तभी शुरू हुआ था। श्री गडकरी ने न्हावा शेवा–सेवरी सी–लिंक परियोजनाओं के पर्यावरणीय स्वीकृति दी थी, जो तब से रूकी पड़ी थी जब से मंत्रालय बना था। मुम्बई को सुख–चैन की नगरी बनाना था उनका सपना, परन्तु दुर्भाग्य से, स्थिति दूसरी तरफ मुड़ गई।
- श्री गडकरी ने पीडब्ल्यूडी को चुस्त दुरूस्त किया और इस सरकारी विभाग में पहली बार कम्प्यूटर का उपयोग शुरू हुआ। उनके कार्यकाल के कर्मचारियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तरह काम करना शुरू किया। सड़कों पर बड़ी संख्या में घातक दुर्घटनाओं को देखते हुए श्री गडकरी ने महाराष्ट्र में दुर्घटना–वाले स्थलों के अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई। इसने लगभग 25000 स्थलों की पहचान की जहां दुर्घटना में मूल्यवान जीवन समाप्त हो जाते थे। उन्होंने प्रारम्भिक रूप से 20 करोड़ के बजट से समिति की सिफारिशों को अमल में लाया। तुरंत ही दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई। इस प्रकार का काम न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि भारत में पहली बार सम्पन्न हुआ। 250 करोड़ रूपए से अधिक खर्च कर पीडब्ल्यूडी ने इन अत्यंत खतरनाक स्थलों को सुधारा।
- महाराष्ट्र विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री गडकरी ने सदा ही सरकार को कटघरे में खड़ा रखा है। उन्होंने अनेकों बड़े–बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया और सदन में बड़े–बड़े मुद्दे उठाए। उन्हें नवम्बर 2004 में भाजपा का महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष चुना गया और दिसम्बर 2006 मं उनका पुनर्निवाचन हुआ। नीचे से ऊपर तक पार्टी संगठन का पुनर्निमाण उनके लिए प्रथम चुनौती थी। श्रीगडकरी ने अपने कठोर परिश्रम से कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा किया और कामकाज को पारदर्शी बनाया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने महाराष्ट्र के कोने–कोने में अपना विस्तार किया। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम अपने क्षेत्र में एक सामाजिक/स्वैच्छिक परियोजना से सहबद्ध होना चाहिए, और इससे अच्छा लाभ मिला। लोगों तक पहुंच बनाने से पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया में तेजी आई है।
- श्री गडकरी का अपवंचितों को शक्तिशाली बनाने में बहुत गहरा योगदान किया है। पार्टी की विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और भारत के प्रति उनका प्रेम सर्वोपरि रहा है। नेतृत्व को उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि वे पार्टी को वर्तमान स्थिति से उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने में सफल होंगे। वे जनता जर्नादन के सच्चे नेता हैं जिस पर पार्टी को गर्व है। ■

*पूर्व प्रधानमंत्री मा. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनके निवास पर बधाई देने पहुंचे श्री लालकृष्ण आडवाणी, रा.स्व.संघ के सहसरकर्यवाह श्री सुरेश सोनी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, श्री अनंत कुमार एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह*

# राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा, सुशासन साधन, अंत्योदय उद्देश्य : गडकरी

Hkk रतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली प्रेस कांफ्रेस में राष्ट्रीय मीडिया जगत के मित्रों से मिलने पर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को आनंददायी क्रिसमस दिवस की और समृद्ध – 2010 की शुभकामना देना चाहता हूं। मैं हमारे प्रेरणास्रोत आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उनके दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना भी करता हूं।

पार्टी द्वारा इस नए महान उत्तरदायित्व को सौंप कर जो भरोसा और विश्वास मुझ में व्यक्त किया गया है, उससे मैं पूर्णतः अभिभूत हूं। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है कि मेरे कंधों पर एक भारी उत्तरदायित्व आ गया है। किंतु, मेरी पार्टी के किसी भी निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं है, यदि वह पार्टी की मूल विचारधारा और आदर्शवाद के प्रति निष्ठावान रहने का संकल्प ले लेता है जैसाकि डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में साक्षात अभिव्यक्त हुआ था; यदि वह हमारे समकालीन दो शीर्षस्थ नेताओं – श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल .ष्ण आडवाणी की प्रेरणादायी विरासत से निर्देशित होता रहता है, यदि वह टीम वर्क और अनुशासन के माहौल में अपने से वरिष्ठ तथा कनिष्ठ सहयोगियों से सीखने की उत्सुकता दर्शाता है जोकि भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सदैव से ही परंपरा रही है, और यदि वह अपने साथी कार्यकर्ताओं की विराट सेना, जिसमें पार्टी की सबसे छोटी और दूरस्थ इकाइयों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, से शक्ति ग्रहण करता है तथा बदले में उन्हें शक्ति प्रदान करता है।

मैं प्रथम और सर्वप्रथम एक कार्यकर्ता हूं। मैं जानता हूं और आज इसकी पुनः



***भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 24 दिसम्बर, 2009 को नई दिल्ली में अपनी पहली प्रेस कांफ्रेस में जारी किया गया वक्तव्य***

पुष्टि करता हूं कि मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की राष्ट्र तथा पार्टी के लिए अथक त्याग–भावना और संघर्ष मेरी पार्टी की दृढ़ता के सबसे बड़े आधार हैं। जहां तक संगठन का सवाल है अनुशासन, दृढ़ संकल्प, परस्पर विश्वास एवं सम्मान यह हमारी कार्य पद्धति की आधारशिला होगी।

**विचारधारा का आधार राष्ट्रवाद :**

भाजपा 'भारत प्रथम' सूत्र पर काम करने वाला दल है। हम भाजपा को राष्ट्र निर्माण के एक उपकरण के रूप में देखते हैं।

मेरी पार्टी की विचारधारा का आधार राष्ट्रवाद था, राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद रहेगा और यही मेरी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रेरणास्रोत भी बना रहेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति में निहित हैं, जो समावेशी भी है और समन्वित भी और वही प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय की प्रेरणा का स्रोत भी है। भाजपा वास्तविक सर्वधर्मसमभाव के प्रति प्रतिबद्ध है, वोट–बैंक की पंथ निरपेक्षता के जैसी नहीं। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा नस्ल के आधार पर भारत के नागरिकों के बीच भिन्नता और भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत सबका है और सभी भारत के, सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही सभी का भारत को सुदृढ़ और एकी.त बनाने का समान दायित्व भी है।

अतः भाजपा उस हर नीति और उस हर प्रयास का विरोध करती रहेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना हो। हमारा विरोध जम्मू और कश्मीर में पनपता अलगाववाद तथा असम एवं देश के अन्य भागों में अवैध घुसपैठ, जिसे कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के तहत प्रोत्साहित किया है के प्रति हमारा विरोध भारत की एकता और सुरक्षा के लिए सदैव है।

**आतंकवाद और नक्सलवाद का संपूर्ण विरोध :**

भारत की एकता और सुरक्षा के प्रति ऐसी ही चिंता मुझे आज अपनी पार्टी की वही अविचल स्थिति स्पष्ट करने के लिए विवश कर रही है कि भारत को आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमलों में लिप्त डेविड कोलमैन हेडली जैसे अंतर्राष्ट्रीय जेहादी षड्यंत्रकारी द्वारा भारत के खुफिया भेद लेने के लिए बार–बार किए गए दौरों के बारे में हाल के खुलासों और प्रधान कमेटी रिपोर्ट में निकाले गए चिंताजनक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हमारी सुरक्षा प्रणाली में ऐसी खामियां मौजूद हैं, जिनका लाभ राष्ट्र के शत्रु कभी भी उठा

सकते हैं। आतंकवाद की तरह ही माओवाद की राष्ट्र विरोधी विदेशी विचारधारा से प्रोत्साहित हुआ नक्सलवाद भी अनेक अबोध जिंदगियों को निगल रहा है, जिसमें हमारे सुरक्षाकर्मियों की जिंदगियां भी शामिल हैं। मेरा संप्रग सरकार से अनुरोध है कि वह इस दोहरे संकट के साथ दृढ़ता से निपटे और मैं इस दिशा में उठाए गए हर उचित कदम के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन का विश्वास व्यक्त करता हूं।

**राजनीति, सामाजिक-आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण का साधन :**

जहां मैं राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हूं, जिसने मुझे राजनीति की तरफ आकर्षित किया है, वहीं भारत की समृद्धि और इसके सभी लोगों के कल्याण मेरे वैचारिक विश्वास के मूल में है। सार्वजनिक जीवन में मेरे बाद के अनुभव और विधायक तथा मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल ने मेरे इस विश्वास को और अधिक दृढ़ कर दिया है कि राजनीति शक्ति हेतु छीना–झपटी का मैदान नहीं बन सकती, बल्कि इसको सामाजिक–आर्थिक सुधार और राष्ट्र–निर्माण का साधन बनना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह समय आ पहुंचा है जब भारत को विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। भाजपा का समतावादी विकास में विश्वास है। इसकी प्राप्ति के लिए हमारी पार्टी आंतरिक निष्पादन परीक्षा–तंत्र विकसित करने का प्रयास करेगी, ताकि जहां–जहां भी भाजपा सत्ता में है वहां–वहां हर स्तर पर सुशासन सुनिश्चित हो सके।

खेद की बात है कि कांग्रेस ने उस पथ का अनुसरण किया है, "जहां कुछ लोगों का विकास हो तथा शेष वंचित"। यह निश्चय ही असमर्थनीय भी है और खतरनाक रूप से अस्थिरकारी भी। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति का हाल का यह खुलासा चेतावनी का संकेत है कि भारत में गरीबों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि ग्रामीण भारत में गरीबी 42 प्रतिशत है न कि 28 प्रतिशत जैसाकि पूर्व में अनुमान लगाया गया था। गरीब लोगों और मध्यम वर्ग के लोगों की दुर्दशा को आसमान छूती मूल्यवृद्धि ने और अधिक बढ़ा दिया है – उस दुर्दशा को जिस पर काबू पाने में संप्रग पूरी तरह विफल हुआ है।

इस वास्तविकता को बदलना किसी भी राजनीतिक स्थापना का पहला कर्तव्य होता है। अतः मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वे अपने वंचित भाई–बंधुओं के चेहरों पर मुस्कान लाने की इच्छा से अभिप्रेरित हों, वे उन किसानों का संकट समाप्त करें, जिन्होंने हजारों की संख्या में आत्महत्याएं कर ली हैं, वे उस कुपोषण का उन्मूलन करें, जो हजारों जनजातीय बच्चों को काल का ग्रास बना रहा है, वे हमारे प्रतिभाशाली युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें।

***मेरा उद्देश्य यह देखना है कि आगामी तीन वर्षों में भाजपा उन राज्यों में, जहां वह पारंपरिक रूप से सुस्थापित है और जहां उसकी अब तक उपस्थिति हाशिये पर बनी हुई है, और अधिक मजबूत बनकर उभरे। इसी के साथ–साथ भाजपा राजग को और अधिक विस्तार देने तथा मजबूत करने के लिए भी प्रयास करेगी ताकि वह प्रतिपक्ष की एकता हेतु एक मजबूत मंच बन सके।***

**अंत्योदय के प्रति प्रतिबद्धता :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शितापूर्ण प्रधानमंत्रित्व के अंतर्गत भाजपा–नीत राजग सरकार ने जनादेश का विकास की गति बढ़ाने तथा उसे व्यापक करने के लिए उपयोग किया था। आज मैं अपनी पार्टी के विकास दर्शन को निम्नलिखित नारे में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना चाहूंगा : राष्ट्रवाद अब हमारी प्रेरणा है, सुशासन द्वारा विकास हमारा साधन है और अंत्योदय (जिसका अर्थ है पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े तथा अन्य दुर्बल वर्गों सहित अत्यधिक वंचित लोगों को अग्रता प्रदान करना) हमारा उद्देश्य है। इस नारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की ठोस अभिव्यक्ति के रूप में भाजपा के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने कार्यक्षेत्र में कम से कम एक विकास और सेवा प्रकल्प से संबद्ध हो।

**आगामी तीन वर्षों में भाजपा सुदृढ़तर होकर उभरेगी :**

मैं इस बात को अधोरेखित करना चाहूंगा भाजपा सुशासन, गतिशील तथा सर्वसमावेशक विकास और आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को प्रतिबद्ध एक स्वाभाविक शासक दल है। कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। भाजपा को गर्व है कि उसने भारत के राजतंत्र को कांग्रेस की प्रधानता वाली एक ध्रुवीय प्रणाली से दो ध्रुवीय प्रणाली में रूपांतरित कर दिया है। भाजपा को इस बात पर भी गर्व है कि उसने उस राष्ट्रीय जनतांत्रिक का गठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसने ऐसा प्लेटफार्म प्रदान किया, जिस पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से इतर सभी पार्टियों का स्वागत हुआ था। मेरा उद्देश्य यह देखना है कि आगामी तीन वर्षों में भाजपा उन राज्यों में, जहां वह पारंपरिक रूप से सुस्थापित है और जहां उसकी अब तक उपस्थिति हाशिये पर बनी हुई है, और अधिक मजबूत बनकर उभरे। इसी के साथ–साथ भाजपा राजग को और अधिक विस्तार देने तथा मजबूत करने के लिए भी प्रयास करेगी ताकि वह प्रतिपक्ष की एकता हेतु एक मजबूत मंच बन सके।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली अपेक्षा यह है कि सभी स्तर पर भाजपा का पार्टी संगठन मजबूत हो। पार्टी का भौगोलिक विस्तार करना और उसको और अधिक एकत्व तथा मजबूती प्रदान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी।

अंततः जो लोग मुझे पुष्प या पुष्पहार देना चाहते है उनसे मेरी अपील है कि उतनी धन राशि किसान सहायता कोष में जमा करें, जिसे आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाए। ■

# चीन की गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय : डा. मुरली मनोहर जोशी

***गत 9 दिसम्बर, 2009 को लोकसभा में "हाल में हुई घटनाओं के संदर्भ में भारत–चीन संबंधों के बारे में" हुई चर्चा की शुरूआत वरिष्ठ भाजपा सांसद डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने की। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं:–***

भारत और चीन में पुराने जमाने से ही सांस्कृतिक, दार्शनिक और वाणिज्यिक संबंध रहे हैं। जब चीन एक उपनिवेश बना तो उस समय भी हमने स्वयं उपनिवेश रहते हुए भी चीन की सहायता की। भारत ने चीन के प्रति हमेशा सदिच्छा ही प्रदर्शित की।

1949 में चीन मुक्त हुआ। चीन में कोई डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन नहीं हुई थी फिर भी भारत ने सब से पहले चीन देश को मान्यता दी। हमने पुराने रिश्तों को देखते हुए संबंध कायम किए और इस बात का ध्यान नहीं किया कि चीन आगे क्या प्रतिदान करेगा। चीन ने प्रतिदान में हमें कभी कुछ नहीं दिया और न आज दे रहा है। हमने पहली गलती उस समय की जब तिब्बत के मामले में हमने बहुत ढील बरती और तिब्बत चीन को दे दिया। सरकार पटेल ने उस समय इस नीति का विरोध किया था और उसके खतरों से देश को सावधान किया था। हम भूल गए कि चीन का सोचने का अपना तरीका है। चीन सदियों की वैश्विक दृष्टि रखता है जबकि हमारे देश में पांच वर्षीय योजना चलती है। 1959 में दलाईलामा के तिब्बत से आने के बाद हालात और बिगड़ गए। हमने दलाईलामा को शरण दी, ठीक किया। हमने अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाया है। वर्ष 1962 तक हमारी नजर सिर्फ पाकिस्तान पर थी। वर्ष 1962 में चीन ने हम पर हमला किया। हम समझ नहीं पा रहे थे कि जिस देश के साथ हमने इतने अच्छे संबंध रखे, उसने ऐसा क्यों किया? वह यह समझता था कि इस भारत को सबक सिखाना है। यह अपने आपको हमसे आगे ले जाना चाहता है। हम आगे नहीं ले जाने देंगे और भारत को सबक सिखाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, चूंकि वरना और कोई ऐसा स्पष्ट सामने आने वाला कारण दिखाई नहीं देता कि चीन ने हमला किया और वह वापस चला गया। वर्ष 1962 से 1976 तक हम चीन के साथ ठंडे रहे। वर्ष 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी थी, तब विदेश मंत्री के नाते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहले चीन गए। इससे पहले कि संबंधों में कुछ गर्माहट आती, चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया और वाजपेयी जी को लौटकर आना पड़ा। वर्ष 1988 में स्वर्गीय राजीव गांधी वहां गए, उससे एक नया रास्ता खुलने की बात आयी, संबंधों में कुछ नरमाहट आनी शुरू हुई। इसके बाद वर्ष 2003 में वाजपेयी जी की यात्रा हुई, जिसमें सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग माना गया। लेकिन इस बीच में जो चीन की आर्थिक और सामरिक प्रगति हुई और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हुआ, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। अमेरिका ने चीन के साथ संबंध बढ़ाये और उसमें पाकिस्तान की मदद ली। एक नया इक्वेशन अमेरिका–पाकिस्तान और चीन का अंदरखाने बना। हम यह समझते रहे कि अमेरिका, पाकिस्तान के मामले में हमारे साथ है। अमेरिका और चीन किसी पॉलीटिकल सिस्टम से बंधे हुए नहीं है। इनके इकोनोमिक, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। लेकिन हमने इस तरफ बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या हो रहा है। नतीजा यह हुआ के हम चीन के बारे में कोई कारगर प्रभावकारी और लम्बे समय की नीति नहीं बना सके। पिछले दो–तीन साल से यह बात बराबर आ रही है कि चीन फिर से एग्रेसिव हो गया है। चीन ने सबसे पहले तो अभी एनएसजी ग्रुप में हमारा विरोध किया और यह कोशिश की कि हमारा वह समझौता सफल न होने पाए। फिर उसने एडीबी और वर्ल्ड बैंक से हमें जो धनराशि मिलनी है, उसके बारे में अडंगा लगाया। क्या वे फिर से यह दिखाना चाहते हैं कि चीन भारत से आगे है, भारत को चीन के समकक्ष बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह वही चीन है जिसने पाकिस्तान को परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित किया, पैसा दिया और टैक्नालॉजी दी। अमेरिका और चीन दानों ही नोन–प्रोलिफेशन ट्रीटी के बड़े भारी पेरोकार रहे हैं, लेकिन उनकी यह बात कहां गई? अमेरिका भी काबिले इत्मिनान साबित नहीं हुआ। वह हमारे साथ स्ट्रेटिजिक दोस्ती की बात तो रकता है लेकिन वह अपनी स्ट्रेटजी, जो उसके राष्ट्रीय हितों के लिए है, उसके साथ चल रहा है। आज परिस्थिति बदल गयी है। चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत जुड़ी हुई है। इसलिए एक मंदी से ग्रस्त, नौकरियों से त्रस्त अभावग्रस्त अमेरिका चीन को नाराज नहीं कर सकता। इसलिए अब यह न समझा जाए कि सन् 1962 की तरह अमेरिका

हमारी मदद के लिए फिर तैयार होगा। आज जो नई–नई परिस्थितियों आ गई हैं, इनमें भारत और चीन के संबंधों में कोई गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या हम उसी तरह से गाफिल बने रहेंगे? हमारे कुछ मित्र तो कहते हैं कि चीन कुछ कर ही नहीं सकता। 1962 में भी जब उसने हमला किया था तो हमारे मित्र इसी सदन के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि चीन तो कभी हमलावर हो ही नहीं सकता, लेकिन हमला हुआ।

अब क्यों इतने इन्कर्शन्स हो रहे हैं? वर्ष 2008 में 200 से अधिक इन्कर्शन हुए हैं। सरकार कह देती है कि यह तो मामूली बात है, ऐसी बातें होती रहती हैं इनकी फिक्र मत कीजिए। आम देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए कि चीन दलाई लामा के तवांग जाने पर आपत्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की अरूणाचल प्रदेश की यात्रा पर आपत्ति कर रहा है। चीन कश्मीर के लोगों को पेपर वीजा देता है। ऐसा चीन क्यों कर रहा है? चीन अरूणाचल प्रदेश को भारत अंग नहीं मानता है। आप इसे बारे में क्या कर रहे हैं? आपने इसे क्यों नहीं रोका, आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों दब रहे हैं, आपको चिंता किस बात की है? चीन सारे दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ वह पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। देश का राजनैतिक प्रभाव घट रहा है। चीन के बारे में हमारी क्या नीति है? चीन आपकी सीमाओं पर पूरी तैयारी के साथ आ रहा है, लॉजिस्टिकली आपसे आगे हो गया है। ये ऐसे सवाल हैं जो देश की सुरक्षा से, देश के भविष्य से संबंधित हैं। कम से कम चीन और पाकिस्तान के मामले में जो आपकी नीतियां हैं, उससे तों हमें यह विश्वास नहीं होता है कि आप भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। आपने दुनिया में कौन से मित्र बनाये हैं? मैं समझता हूं कि चीन आपके ऊपर आर्थिक आक्रमण भी कर रहा है। चीन ने आपके बाजार में ऐसी तमाम चीजें भेजी हैं, जो हमारे बाजार के लिए हानिकारक हैं। आपने बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध लगाया है, लगाना चाहिए। इस बारे में भी शंकायें प्रकट की जा रही हैं कि जो बहुत सी जाली करेंसी हमारे यहां आती है उसमें भी चीन का हाथ है। फिर से नेपाल के अंदर उपद्रव हो रहा है और जो असम के अंदर उपद्रव हो रहा है और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि उल्फा के जो लोग हैं, अब वे भागकर चीन चलग गए हैं।

चीन आपके देश की इन सारी विरोधी गतिविधियों का समर्थन कर रहा है, आप क्या का रहे हैं? अगर चीन अरूणाचल की बात करता है, तो हमें तिब्बत ऑटोनोमस रीजन की बात उठानी चाहिए। हम इसे क्यों नहीं उठाते हैं, हम क्यों डर रहे हैं? इस देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं? नए समीकरण बन रहे हैं। इस बात की संभावनाओं से मुझे इन्कार नहीं है कि कल चीन और अमेरिका के बीच में सारी दुनिया को आपस में बांट लेने की संधि न हो जाए। मेरा निवेदन है कि भारत और चीन के संबंधों पर आपको इस सदन को और देश को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। ■

# राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना आवश्यक : यशवंत सिन्हा

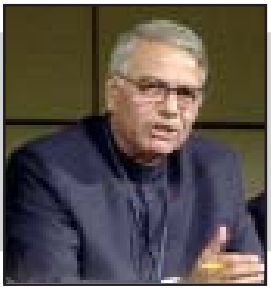

***गत 10 दिसम्बर, 2009 को लोकसभा में ''अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2009–10'' पर हुई चर्चा की शुरूआत भाजपा सांसद श्री यशवंत सिन्हा ने की। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं:***

मैं बधाई देता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में निवल नकद निकासी केवल 25000 करोड़ रूपए के लगभग सीमित है। गत वर्ष पूर्ववर्ती वित्त मंत्री द्वारा एकदम गलत अनुदानों की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत किए जाने की तुलना में इसमें बहुत राहत मिली हैं। परन्तु बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिनका बजट तैयार करते समय आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था। उदाहरणस्वरूप एयर इंडिया को नई इक्विटी के रूप में 800 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं। एयर इंडिया को 7000 करोड़ रूपए का घाटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक यह 800 करोड़ रूपया एयर इंडिया की मदद करेगा। एयर इंडिया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बड़ी विफलता और सरकार के कुप्रबंधन को दर्शाता है। तत्पश्चात् उर्वरक राजसहायता, भारती खाद्य निगम को राजसहायता, पेंशन पर अतिरिक्त व्यय जैसे मुद्दों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। मैं इस बात पर सहमत हूं कि वर्तमान वित्त मंत्री को अपने पूर्ववर्ती की ओर से यह गड़बड़ियां विरासत में मिली थीं। जो संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं वह हमारा अपना बनाया हुआ है। यह रिकार्ड की बात है कि वैश्विक वित्तीय संकट बहुत बाद में आया जबकि हमने स्वयं पहले ही संकट सृजित कर लिया था। हम चीन उद्योग की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। इस संबंध में लोगों में यह संदेश गया है कि जहां सरकार 35–40 रूपए प्रति किलो चीनी

खुदरा बाजार में बिकवा रही है। वहीं गन्ना किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। तथ्य यह है कि न केवल चीनी की बल्कि सभी चीजों की कमी है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि देश में एलपीजी की कमी कैसे हो रही है। जब हम शासन में थे तब एलपीजी सिलेंडर घरों तक पहुंचाए जाते थे। आज एक महीने से ज्यादा का इंतजार करना पडता है। यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होनी है तो वित्त मंत्री को इन समस्याओं से निपटना होगा और भारत की जनता को सम्मान और आराम की जिंदगी प्रदान करनी होगी। मुझे आज ऐसा लगता है कि वित्तमंत्री के समक्ष सबसे बड़ी समस्या खाद्य मूल्यों में अनियंत्रित वृद्धि है। स्वयं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट मं कहा गया है कि घरेलू मोर्चे पर खाद्यान्नों, विशेषकर चावल और दालें, अन्य प्राथमिक खाद्य उत्पाद और चीनी के मूल्यों में वृद्धि नीतिगत चिंता के प्रमुख विषय हैं। जब गत वर्ष मूल्य बढ़ने लगे थे तब हमने सरकार को सलाह दी थी कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों से समस्याएं और बढ़ेंगी। कठोर मौद्रिक उपायों से धन की कमी हुई जिससे ब्याज बढ़ गया और समस्याएं बढ़ीं। वैश्विक संकट ने इसको और बढ़ाया। आपकी अर्थव्यवस्था लगभग 8 प्रतिशत की दर से कैसे बढ़ रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू बचत और घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को स्मरण करना चाहूंगा कि वर्ष 2002 में इस देश ने भयंकर सूखे का सामना किया था। देश के लोगों को इसका पता भी नहीं चला क्योंकि हमारे गोदामों में 65 मिलियन टन खाद्यान्न भरा पड़ा था। सरकार को गोदामों से खाद्यान्न बाहर निकालने में संकोच नहीं करना चाहिए। सरकार को नरेगा के अंतर्गत मजदूरी के एक अंश के रूप में खाद्यान्न प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। हफ्ते–दर–हफ्ते इस प्रकार की मूल्य वृद्धि स्वीकार्य नहीं है। खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने में सरकार द्वारा विफलता दर्शाने को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उनके पास सभी यंत्र मौजूद हैं। जब भी हम आम जनता के बीच जाते हैं तो वे हमें वृद्धि का स्मरण कराते हैं। मैं सरकार से आशा करूंगा कि वह आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के नियंत्रण के बारे में सकारात्मक उत्तर दें। आप विभिन्न प्रकार के बांड कैसे जारी कर रहे हैं? इसका अर्थ है कि सरकार अपने वित्तीय घाटे में स्वयं बढ़ोतरी कर रही है। तब भी वित्तमंत्री को अपना वित्तीय घाटा बजट का लगभग 6 प्रतिशत ही रखा। तत्पश्चात् सौभाग्यवश सरकार की सहायता के लिए वैश्विक वित्तीय संकट आ गया जो उनकी सभी विफलताओं को छुपा गया। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यह सारा प्रयास चुनाव जीतने के लिए किया गया। वित्तमंत्री ने कहा था कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए हमें इसी वर्ष के दौरान संस्थागत सुधार के उपाय करने होंगे। ऐसा उदाहरण कहां है कि इस तरह के उपाय पर सोचा भी गया हो। ऋण–सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात सभी तर्कसंगत सीमाओं को पार कर गया है। इसे अनुकूल स्थिति नहीं कहा जा सकता। स्थिति यह है कि आपका खर्च बढ़ता जाएगा जबकि करों से होने वाली आय कम होती जाएगी। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का क्या हुआ, जिसे हमने तब पारित किया था जब हम सत्ता में थे। मैं इस सभा में कह सकता हूं कि पिछले पांच–छह वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। यदि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 15 प्रतिशत भी बढ़ा देती और यदि यह पैसा आधारभूत ढांचे के सृजन के लिए जाता तो मैं इस सभा में खड़े होकर बधाई देने वाला पहला व्यक्ति होता।

जो लोग वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें बीपीएल कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह बजट का प्रबंधन करे और इसे संतुलित करे तथा वह निर्धन व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान देने का प्रयास करे। ■

*झारखण्ड विधानसभा चुनाव*

## झारखण्ड में फिर से त्रिशंकु विधानसभा

# किसी को बहुमत नहीं

साल भर के राष्ट्रपति शासन और कोड़ा के कारनामों की गूंज के बीच हुए विधानसभा चुनाव में वोटरों ने निर्णायक फैसला नहीं सुनाया। पिछली बार पांच निर्दलीय सत्ता के केंद्र में पांच पांडव के रूप में चर्चित हुए तो इस बार विधानसभा पूरी तरह त्रिशंकु सामने आई। गठबंधन के रूप में 25 सीटें हासिल कर कांग्रेस–झाविमो अव्वल जरूर रहे, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में दो दावेदार सामने आ गए, भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोनों को 18.18 सीटें मिली हैं। नई–नवेली पार्टी लेकर मैदान में कूदे बाबूलाल मरांडी ने जबर्दस्त प्रदर्शन दिखाया, उनको 11 सीटों पर जीत मिली। झामुमो ने संप्रग से अलग होकर चुनाव लड़ा और पिछले प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों की संख्या 18 पहुंचा ली। विधानसभा की जो तस्वीर उभरी है, उसमें कोई भी सरकार गठबंधन के बगैर बनती नहीं दिख रही। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 विधायकों की जरूरत होगी। गत लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित भाजपा बहुमत तक या सबसे बड़े दल के रूप में देख रही थी लेकिन उसे 2005 के मुकाबले 12 सीटें कम मिलीं। कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 16 विधायकों की जरूरत पड़ेगी जबकि भाजपा–झामुमो का गठजोड़ होता है तो केवल तीन विधायकों की कमी रह जाती है क्योंकि दो सीटें जदयू के पास हैं। जदयू को पिछली बार छह सीटें मिली थीं। सत्ता संघर्ष के बीच तोड़फोड़ की आशंका से छोटे–बड़े सभी दल आशंकित हैं।

| | |
|---|---|
| dy lhVs | 81 |
| भाजपा | 18 |
| झामुमो | 18 |
| कांग्रेस | 14 |
| झाविमो | 11 |
| राजद | 05 |
| आजसू | 05 |
| जदयू | 02 |
| निर्दलीय | 08 |
| ?kkf"kr ifj.kke | 81 ■ |

# राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल तो सत्तारूढ़ पार्टी कर रही है : एम. वेंकैया नायडू

*गत 9 दिसम्बर को राज्यसभा में जाने ''लिब्रहान आयोग का प्रतिवेदन और बाबरी मस्जिद मामले का विचारण'' पर हुयी अल्पकालिक चर्चा में वरिष्ठ भाजपा नेता श्री वेंकैया नायडू ने भाग लिया। हम यहां उनके भाषण का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं:–*

श्रीमती गांधी की मृत्यु के साथ ही उनके पुत्र प्रधानमंत्री बने और उनके अन्य साथियों ने अयोध्या मामले को संभाला। तब से अनेक विनाशकारी कदम उठाए गए। ताला खोले जाने के फलस्वरूप अत्यधिक विवाद उत्पन्न हुआ। न्यायालय द्वारा आदेश जारी करने के कुछ घंटों में ही मंदिर का ताला खोल दिया गया और दूरदर्शन के कैमरामैन इस अवसर पर मौजूद थे।

यदि यह निर्णय गलत था तो आपमें से किसी में भी खड़े होकर यह कहने का साहस नहीं था कि यह गलत निर्णय है। वर्तमान गृहमंत्री, प्रधानमंत्री यहां तक कि अनेक मंत्री, ये सभी उस सरकार में शामिल थे। उस समय आप सब शांत थे। अचानक अब आपको याद आया कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। आप देश में किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रतिवेदन का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सभी ने इस प्रतिवेदन की निन्दा की है। इस दस्तावेज की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। यह राजनीति और देश के सार्वजनिक जीवन के मूल तत्वों की जानकारी के बगैर राजनीति, उपदेशों और शिक्षाओं से भरा हुआ है। मुझे हैरानी है कि यह प्रतिवेदन किसने तैयार किया है। इस प्रतिवेदन में इतनी सारी तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। वह ये नहीं जानते कि आरएसएस की स्थापना कब हुई। उन्हें यह नहीं पता कि आरएसएस के संस्थापक कौन थे। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक का नाम स्वयं ही रख दिया। उनके निष्कर्ष साक्ष्य के विपरीत हैं। इतने वर्षों तक यह व्यक्ति क्या कर रहा था? इसके विपरीत शाह आयोग को लीजिए। एक वर्ष और पांच माह के भीतर इसका प्रतिवेदन तैयार करके सरकार को दे दिया गया था। लिब्रहान प्रतिवेदन वोट बैंक की राजनीति हेतु प्रतिवेदन है। पूरा प्रतिवेदन त्रुटियों से भरा हुआ है। यहां–वहां कुछ छोटी, व्याकरण संबंधी अथवा कुछ ऐतिहासिक त्रुटियों के बारे में तो समझा जा सकता है परन्तु हर मोर्चे पर पूर्णतया अनभिज्ञता दिखाई गई है। श्री लिब्रहान, ने जांच आयोगों की साख धूल में मिला दी है और भविष्य में कोई भी किसी जांच आयोग के गठन की मांग नहीं करेगा। इस देश के लिए की गई यह उनकी सर्वोत्तम सेवा है।

इससे पहले कि गृहमंत्री सभा में कोई वक्तव्य दें, सबसे पहले उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह प्रतिवेदन कैसे लीक हुआ। इसकी प्रति पत्रकारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक कहां से पहुंची? गृहमंत्री को पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके सभा में आना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुद्दों की ओर से ध्यान हटाने के लिए, मधु कोडा, मूल्य वृद्धि और उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों के गन्ना किसानों की दशा से ध्यान हटाने के लिए प्रतिवेदन के कुछ चुनिंदा हिस्सों को लीक किया गया था। आप सभा में आकर अपनी बात कह सकते थे। इसके बजाए आपने मीडिया में कुछ चुनिंदा मित्रों तक इसे पहुंचाया और संसद को मजाक बना दिया गया। यह प्रतिवेदन देश के उच्चतम न्यायालय की अवमानना करता है। आपने उच्चतम न्यायालय की अवमानना की, आपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री की अवमानना की, आपने प्रत्येक संस्थान, देश के सभी साधु संतों की अवमानना की है।

अब, तथाकथित षड्यंत्र के मुद्दे पर बात करे, तो श्री लिब्रहान इस तथ्य को साबित करने में विफल रहे हैं। अयोध्या के संबंध में कांग्रेस का श्वेतपत्र कहता है कि कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री के पिता, गृह मंत्री, श्री एस.बी. चह्वाण कहते हैं कि कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। आईबी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोई षड्यंत्र नहीं हुआ। सीबीआई ने किसी षड्यंत्र से इनकार किया है और दायर किए गए आरोप–पत्र में षड्यंत्र का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आरएसएस पर प्रतिबंध के बोर में विचार–विमर्श करने के लिए सरकार द्वारा गठित बाहरी अधिकरण का निष्कर्ष है कि किसी षड्यंत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है तथा आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथ–पत्र दायर किया जिसमें कहा गया है कि यह गलत है कि अयोध्या में ढांचे को किसी विशेष समुदाय अथवा राजनीतिक दल द्वारा रचे गये आपराधिक षड्यंत्र के तहत गिराया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद आदेश को उच्चतम

न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया। उसने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

हमें इन लोगों से किसी प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के मन में वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। अयोध्या में 20 और मस्जिदें हैं। इनमें से किसी को भी छुआ नहीं गया। भाजपा का मानना है कि हमारे इतिहास में धर्मतंत्र का कोई स्थान नहीं रहा है। भारत किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशेष सरकार की वजह से धर्म–निरपेक्ष नहीं है। यह इस देश के लोगों के रक्त के कारण धर्म–निरपेक्ष है। इस देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कुछ लोग उपदेश देने, सबक सिखाने और लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। राम को विश्व में सब जगह आदर दिया जाता है। इसीलिए, महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की थी। आप लोग हमारा उपहास करते उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक मानसिकता के लोग हैं। क्या राम के बारे में बात करना साम्प्रदायिक मानसिकता है? आपकी सरकार में ऐसे लोग आपका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने राम का उपहास किया, जिन्होंने रामसेतु का उपहास किया।

इस ढांचे को भारत के लोगों ने गिराया। इनमें भारत के सभी वर्गों के लोग, कार सेवक और वहां एकत्र अन्य लोग शामिल थे। उन सभी ने ऐसा किया क्योंकि इस मामले में वर्षों से विलम्ब हो रहा है और राजनीतिक दल, राजनीतिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ताले खुलवाए। हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नही बल्कि देशभर और विश्व में लोगों की धारणा के बारे में बात करते हैं। क्या हम साम्प्रदायिक लोग हैं। आपका मुस्लिम लीग के साथ दोस्ताना है। आपको उन लोगों के साथ गठबंधन है जिन्होंने वंदे मातरम् का विरोध किया। आप ऐसे काम करते हैं और बदले में इनका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं।

सोमनाथ मंदिर की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति वहां शिलान्यास करने गये थे। क्या वह साम्प्रदायिक थे? आपके नेता वहां जाते हैं, आप शिलान्यास की अनुमति देते हैं, आप गृहमंत्री को वहां भेजते हैं, आपके मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और इसके बाद आप दूरदर्शन पर धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करते हैं और जब हम बात करते हैं तो हम साम्प्रदायिक हो जाते हैं। यदि कोई पार्टी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है तो वह वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है।

हमें बहुमत मिला था। हमने छह वर्ष तक देश पर शासन किया। हमने वायु सम्पर्क, रेल सम्पर्क, राजमार्ग सम्पर्क, ग्रामीण सम्पर्क, दूरसंचार सम्पर्क, टेलीविजन सम्पर्क, पत्तन सम्पर्क और सभी दलों के साथ सम्पर्क बनाया। हमने हर दल को अपने साथ लेकर कार्य किया। हमें साथ रहना है, साथ कार्य करना है। हमें देश को आगे बढ़ाना है। हम लगातार हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर निगाह नहीं रख सकते। हालांकि हमें इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। अयोध्या में अनेक अन्य मंदिर भी हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके केवल इसी मंदिर की बात क्यों करते हैं। हम केवल इसी मंदिर की बात करते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। इस देश में राम का नाम घर–घर में है। राम मर्यादा पुरूषोत्तम हैं। कुछ लोग मेरे नेता के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। मेरे नेता ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की अवधारणा लाकर देश की एकता के हित में देश की सबसे बड़ी सेवा की है। हमें राम जन्मभूमि अभियान से जुड़े होने पर गर्व है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन उसके साथ–साथ हमारे मन में मुसलमानों अथवा ईसाइयों के लिए कोई अनादर नहीं है। हम किसी उचित स्थान पर उनके लिए मस्जिद का निर्माण चाहते हैं। हम उन सभी मंदिरों को सौंपे जाने की मांग नहीं कर रहे हैं जिन्हें पूर्व में नष्ट कर दिया गया था। धर्म–निरपेक्षता का अर्थ अधार्मिकता नहीं होता। धर्म–निरपेक्षता का अर्थ हिन्दू विरोधी नहीं होता। यदि आप हिन्दुत्व की बात करते हैं तो यह गलत है। हिन्दुत्व में क्या गलत है? हिन्दुत्व जीवन शैली है। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है।

***सोमनाथ मंदिर की बात करें, तो भारत के राष्ट्रपति वहां शिलान्यास करने गये थे। क्या वह साम्प्रदायिक थे? आपके नेता वहां जाते हैं, आप शिलान्यास की अनुमति देते हैं, आप गृहमंत्री को वहां भेजते हैं, आपके मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और इसके बाद आप दूरदर्शन पर धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करते हैं और जब हम बात करते हैं तो हम साम्प्रदायिक हो जाते हैं। यदि कोई पार्टी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है तो वह वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है।***

भारत एक है, एक राष्ट्र है और यहां के लोग एक हैं। गोवा की तरह एक सामान्य सिविल कोड देश में यथाशीघ्र सभी लोगों की सहमति से लागू होना चाहिए। लिब्रहान आयोग ने भी उल्लेख किया कि वहां गत 70 वर्षों से कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। आपने वहां एक शिलान्यास किया। आप क्या इस तरह की मानसिकता को जारी रखना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति जारी रखना चाहते हैं अथवा महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान निकालना चाहते हैं। इस मामले का हमेशा के लिए निराकरण कीजिए। यथार्थवादी बनिए। आप यह भलीभांति जानते हैं कि इस संबंध में कोई कुछ नहीं करने वाला है। गत 50 वर्षों से न्यायालयों ने भी इस संबंध में कुछ नहीं किया। यह 2.3 एकड के स्थल के संबंध में विवाद है। देने और लेने का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक साथ रहना चाहते हैं, हम सब एक साथ प्रसन्नता से रहना चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, हम तथाकथित पश्चिमी राष्ट्रों या अन्य राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा करना चाहते है और हम एक सुदृढ़ राष्ट्र बनना चाहते हैं।

इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए, जैसे कि आप उन्हें कुछ देने वाले हैं। चाहे यह अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, सभी इस देश का समान भाग हैं। इसलिए कृपया वहां पर राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए एक उचित वातावरण बनाने की अनुमति दें।■

# कोपेनहेगन समझौता राष्ट्रीय हितों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण समझौता- अरुण जेटली

*गत 23 दिसम्बर 2009 को राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली द्वारा राज्य सभा में 'कोपेनहेगन समझौते' पर दिए भाषण के कुछ प्रमुख चर्चा बिन्दु–*

**कोपेनहेगन समझौता पूरे विश्व के लिए निराशाजनक है।**

यह गरीब और विकासशील देशों के साथ विश्वासघात करता है और विकसित देशों की वादाखिलाफियों को बढ़ाने वाला समझौता है। जो कुछ भी पृथ्वी पर हो रहा है, उसके प्रति जरा भी चिंता नहीं की जा रही है।

कोपेनहेगन में मिले अवसर गंवा देने से अंतर्राष्ट्रीय निराशा पैदा हुई है, उसकी बजाय सरकार ने कहना शुरू कर दिया है कि कोपेनहेगन समझौता भारत और 'बेसिक राष्ट्रों' के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। घुमा–फिरा कर कही गई बात (स्पिन डाक्टरिंग) कभी सत्य का स्थान नहीं ले सकता। 'स्पिन डाक्टरिंग' कभी भी ऐसी प्रतिकूलता का स्थान नहीं ले सकती जिससे प्रकृति, जलवायु और पृथ्वी आहत हुई है।

**क्या क्योटो प्रोटोकाल दफना दिया गया है?**

सरकार ने इस बात पर खुशी प्रगट की है कि क्योटो प्रोटोकाल का त्याग नहीं किया गया है और अब भी इसका अस्तित्व है। परन्तु सच्चाई इसके विपरीत है। ठीक है कि कोपेनहेगन समझौते में विशेष रूप से यह नहीं कहा है कि क्योटो प्रोटोकाल अब 'आप्रेशन' में नहीं रहेगा। किंतु, भले ही अभिव्यक्त रूप में न सही, सांकेतिक रूप में क्योटो प्रोटोकाल परित्यक्त बन चुका है। सांकेतिक परित्यक्ता अभिव्यक्ति परित्यक्तता जैसी ही है। क्योटो प्रोटोकाल में विकसित देशों के लिए अपने उत्सर्जन स्तर को 1990 वाले स्तर से कम से कम 5 प्रतिशत नीचे लाना जरूरी था। क्योटो प्रोटोकाल के अन्तर्गत बाद की बातचीत में विकसित देशों ने स्वयं यह जिम्मा लिया कि वे विश्व में तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के उद्देश्य को देखते हुए 1990 वाले स्तर से 25–40 प्रतिशत तक की उत्सर्जन कटौती करेंगे। किन्तु, विकसित देशों ने ऐसा किया नहीं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने प्रोटोकाल का परित्याग करना चाहा। उन्होंने क्योटो प्रोटोकाल और बाली कार्ययोजना के अन्तर्गत अपने दायित्वों को नहीं निभाया।

अब विकसित देश ऐसी कार्य–प्रणाली प्राप्त करने में सफल हो गए है जो कोपेनहेगन समझौते में क्योटो प्रोटोकाल का विकल्प बनकर आ गई है। अब समझौते के पैराग्राफ 4 में संलग्नक– 1 में विकसित देशों को 2020 तक उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों के बारे में स्वयं को प्रतिबद्ध बनाना है, जिसके सेक्रेटरिएट को 31 जनवरी 2010 को पेश करेंगे। इसे आईएनएफ दस्तावेज के रूस में रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की बोलचाल भाषा में आईएफएफ दस्तावेज केवल सूचनार्थ होता है। कोपेनहेगन समझौते में जिस तथाकथित उत्सर्जन कटौती का जो रास्ता अपनाया गया है, क्या कोई कह सकता है कि क्योटो प्रोटोकाल का अब भी अस्तित्व बना हुआ है? संलग्न 1 में विकसित देश क्योटो प्रोटोकाल और बालीकार्य योजना कानूनी रूप से बंधे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब कोपेनहेगन समझौता और क्योटो प्रोटोकाल के दायित्वों के बीच सम्पूर्ण विरोध की स्थिति बनी हुई है। स्पष्ट है कि कोपेनहेगन समझौता ही ऊपर रहेगा।

**'पीकिंग वर्ष' के बारे में रेड लाइन**

मंत्री महोदय ने संसद को विश्वास दिलाया है कि भारत सरकार कभी भी 'पीकिंग वर्ष' को स्वीकार नहीं करेगी। कोपेनहेगन समझौते के पैरा 2 में 'पीकिंग वर्ष' की बात कही गई है। 'पीकिंग वर्ष' का निर्धारण विकसित देशों के लिए किया जाएगा और विकासशील देशों को कुछ और समय उपलब्ध रहेगा। किन्तु, पीकिंग वर्ष निर्धारण का दायित्व तो स्पष्ट ही है। प्रभावी प्रतिबद्धता यह है: ''हम यह मानते हुए यथा सम्भव ग्लोबल और राष्ट्रीय उत्सर्जन की 'पीकिंग वर्ष को प्राप्त करने में सहयोग करें कि विकासशील देशों के लिए पीकिंग वर्ष का 'टाइम–फ्रेम' अधिक रहेगा।'' अगले दौर की बातचीत में, 31.1.2010 तक प्रतिबद्धताएं पेश करने के बाद विकसित देशों के लिए पीकिंग वर्ष का निर्धारण होगा और विकासशील देशों के लिए पीकिंग वर्ष का 'टाइम फ्रेम' कुछ और लम्बा रहेगा।

**असंपुष्ट घरेलू गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन की अनुमति न देने पर रेड लाइन का उल्लंघन**

भारत सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि असंपुष्ट घरेलू कार्यों को कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय सत्यापन और मानीटरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल भारत सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा इस बारे में उठाए गए स्वैच्छिक उपायों की ही मात्र सूचना दी जाएगी। किंतु कोपेनहेगन समझौते में इस रेड–लाइन का भी उल्लंघन हुआ है। इसमें बहुत कुछ अस्पष्टता है क्योंकि विकसित देश अगले दौर की वार्ता में कह सकते हैं कि हमने तो अंतर्राष्ट्रीय जांच के एक विशेष स्तर की ही बात की थी। संलग्नक 1 और गैर संलग्नक 1 की सभी प्रतिबद्धताएं ये देश 31.1.2010 तक आइएनएफ दस्तावेज के रूप में सेक्रेटरिएट को देंगे। विकसित देशों के मामले में इन प्रतिबद्धताओं की नाप तोल, रिपोटिंग और सत्यापन वर्तमान

तथा आगे बनने वाली गाइडलाइनों के अनुसार किया जाएगा। गैर–संलग्नक–1 के मामले में ये देश, जिनमें भारत भी शामिल है, जो प्रशासक गतिविधियां करते हैं, उन घरेलू गतिविधियों की नाप–तोल, रिपोर्टिंग और सत्यापन होगी जिसका परिणाम यह होगा कि इनकी रिपोर्टिंग हर दो वर्ष के बाद नेशनल कम्युनिकेशन के माध्यमों से होगी। इन गतिविधियों के कार्यान्वयन पर नेशनल कम्युनिकेशन माध्यम से सूचना का संचार होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित गाइडलाइनों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण का प्रावधान होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय सम्प्रभुता का सम्यक किया जाए। इस प्रतिबद्धता में तीन प्रभावी वाक्य है। प्रशासक गतिविधियों की रिपोर्टिंग के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। इन प्रावधानों में शामिल है– (1) अंतर्राष्ट्रीय परामर्श; (2) हमारे किए गए काम का विश्लेषण और (3) इस परामर्श और विश्लेषण की गाइडलाइनों का अंतर्राष्ट्रीय रूप से निर्माण करना, जिसमें हमारी बात बहुत कुछ नहीं चलेगी। प्रशासक गतिविधियों के बारे में मत–विभिन्नता की स्थिति में हम पर व्यापार प्रतिबंध लग सकते हैं। रिपोर्टिंग के साथ ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। जवाबदेही केवल भारतीय संसद तक सीमित नहीं रहती है। असंतुष्ट घरेलू गतिविधियों पर भी हमारी गतिविधियों का अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण होगा। अगर विश्लेषण से पता चलता है कि कहीं कोई खामी है तो हमें दण्ड भुगतान होगा जिसमें व्यापार प्रतिबंध शामिल है।

**क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता और प्रतिबद्धता है?**

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चर्चा हो रही है कि एक बार विकसित देशों तथा बेसिक देशों, जिनमें भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, इस पर सहमत हो जाते हैं तो विकसित देश कमजोर देशों को अपने अनुसार चलने पर और अधिक दबाव डालेंगे। अंततः कोपेनहेगन समझौता दीर्घकालीन एवं बाध्यकारी समझौता बन जाएगा। क्योटो प्रोटोकाल और बाली कार्य योजना के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं के स्थान पर इसकी सम्भावना सत्याभासी समझी जा रही है। इसके अलावा, पैराग्राफ 5 में स्पष्ट ही भारत जैसे देशों की स्पष्ट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। इसमें कहा है– ''सम्मेलन के गैर–संलग्नक–1 देश प्रशासक गतिविधियों को कार्यान्वित करेंगे, जिन्हें 31.1.2010 तक प्रस्तुत किया जाना है। समझौते के परिणाम एकदम स्पष्ट हैं। भारत को जनवरी 2010 के अंत तक प्रशासक गतिविधियां प्रस्तुत करनी हैं। इसमे प्रतिबद्धता है कि भारत जो कुछ करेगा, उसके कार्यान्वयन को प्रस्तुत करना है।'' कार्यान्वयन सम्बंधी सूचना को भेजना ही होगा। घरेलू नाप–तोल, रिपोर्टिंग और विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय परामर्श तथा विश्लेषण की व्यवस्था है। गाइडलाइनों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और विश्लेषण की प्रकृति का निर्धारण है। क्या हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमने कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता नहीं की है? यह शैतानी करतूत तो पूरे विस्तार में मौजूद है और हम इस सच से इंकार नहीं कर सकते कि इस समझौते की ड्राफ्टिंग मे हमें उल्लू बनाया गया है।

**विकासशील और कमजोर देशों को प्रशासक गतिविधियों के लिए प्रतिवर्ष १०० बिलियन डालर कौन देगा?**

ऐसा कुछ भाव बनाया गया है कि इन सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विकसित जगत प्रति वर्ष 100 बिलियन डालर देगा और इन संसाधनों को विकासशील तथा कमजोर देशों में बांटा जाएगा। पैराग्राफ 8 में एक विवरण है कि विकसित देशों के सरकारी स्रोतों से इस धन की उपलब्धता नहीं होगी। पैराग्राफ 8 में कहा है– ''यह धन विभिन्न प्रकार के स्रोतों, पब्लिक आरैर प्राइवेट, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से आएगा जिसमें वित्त के कई विकल्प शामिल हैं। इस धन का बहुत बड़ा भाग विकासशील तथा कमजोर देशों में कार्बन व्यापार के खाते से होने वाली आमदनी से आएगा। यदि पैराग्राफ 8 में इसका उल्लेख न भी होता तो भी यह धन किसी तरह से आना था। व्यापार से होने वाली आमदनी विकसित जगत का धन नहीं है।

इन चिंतादायक विषयों के अलावा भी ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हमारे सामने आते हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख इस प्रकार है:

- प्रस्तावन में बाली कार्य योजना में ''to achieve the ultimate objective'' के स्थान पर 'In pursuit of the ultimate objective' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें बाली कार्य योजना के ''to enable the full, effective and sustained implementation of the convention'' के स्थान और तुलना में ''being guided by this principles and provision of the U.N. Convention'' वाक्य का प्रयोग किया है।
- पैराग्राफ 1 में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ग्लोबल तापमान पर लाने की जरूरत का उल्लेख है इसमें बेस–लाइन के उल्लेख को भुला दिया गया है।
- दस्तावेज में प्रदूषकों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी की बात का जिक्र नहीं है।
- दस्तावेज में प्रतिव्यक्ति या विकासशील एवं गरीब देशों के नागरिकों की किसी बाध्यकारी कार्बन स्पेस का उल्लेख तक नहीं है।
- पैराग्राफ 5 में जानबूझ कर चूक की गई है। गैर–संलग्नक–1 वाले देशों को 31.1.2010 तक अपनी अनुसूचियां जारी करनी है, जैसा कि यूएन कंवेशन के अनुच्छेद 4.1 और अनुच्छेद 4.7 में निहित है, जिनमें यह प्रावधान है कि विकसित जगत की उत्सर्जन कटौती सम्बंधी टेक्नालाजी की पूरी लागत देनी होगी। इसमें अनुच्छेद 4.3 का उल्लेख नहीं है, जिसमें टेक्नालाजी हस्तांतरण की लागत का प्रावधान है।
- दस्तावेज में टेक्नालाजी हस्तांतरण के मामले में आई पीआर अपेक्षाओं की छूट के प्रावधान भी नहीं दिए गए हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अत्यंत संदिग्ध दस्तावेज को राष्ट्रीय उपलब्धि का नाम दिया गया है। जब भारत सरकार राजनैतिक नेतृत्व कोपेनहेगन गया तो विकसित देशों ने निरंतर यह भय फैलाया कि वे अड़ंगे फैलाएंगे। जहां भारत के राष्ट्रीय हितों पर नजर रखने की जरूरत थी वहां विकसित देशों ने इस दबाव पर राजनेताओं का आदर भाव दिखा कर असंतुलित कर दिया।

दुख की बात है कि हमारे राजनैतिक नेतृत्व ने विकसित देशों के इस आदरभाव को भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने से ज्यादा तरजीह दी। ■

# महंगी पड़ती संप्रग सरकार

**& jktho çrki :Mh**

fi छली तिमाही में जब आर्थिक वृद्धि दर 18 माह के सर्वाधिक स्तर 7.9 फीसदी पर पहुंची तो संप्रग सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई, जिसे घुमाकर वह अपने सारे संकट दूर कर सकती है। जिस देश में 22 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है वहां इस 7.9 फीसदी के आंकड़े का क्या महत्व? हम यह भी जानते हैं कि भारत के अस्सी करोड़ लोग 90 रुपये की दैनिक आय से भी कम पर जीवनयापन करते हैं। 40 प्रतिशत बच्चे आज भी अल्पाहार और कुपोषण के शिकार हैं। वर्तमान संप्रग सरकार कभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की दुहाई देकर बचने का प्रयास करती रही है।

***हम यह भी जानते हैं कि भारत के अस्सी करोड़ लोग 90 रुपये की दैनिक आय से भी कम पर जीवनयापन करते हैं। 40 प्रतिशत बच्चे आज भी अल्पाहार और कुपोषण के शिकार हैं। वर्तमान संप्रग सरकार कभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी, कभी सूखा तो कभी बाढ़ की दुहाई देकर बचने का प्रयास करती रही है।***

भारत विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था है। यदि यही विकास दर रही तो आने वाले वर्षों में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हो जाएगी। भारत एक खरब डालर की अर्थव्यवस्था भी है, अर्थात विश्व के गिने–चुने देशों में एक, जिसका सकल घरेलू उत्पाद एक लाख करोड़ डालर से अधिक है। आउटसोर्सिंग में हमें कोई चुनौती देने वाला नहीं है।

साफ्टवेयर उत्पादन में हम अद्वितीय हैं। गेहूं, चावल, गन्ना और कई अन्य फसलों में हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। फिर ऐसा क्यों है कि आधी से अधिक जनता को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता? इस वर्ष ही खाद्य मूल्य दर 15.6 प्रतिशत बढ़ चुकी है। मुद्रास्फीति की दर, जो अक्टूबर में 1.34 प्रतिशत थी, इस वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि देख चुकी है।

खाद्य मुद्रास्फीति तो 13 प्रतिशत से भी ऊपर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकाक के हिसाब से मुद्रास्फीति की दर 8.5 प्रतिशत है। स्मरण रहे कि राजग सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2004 में इसे 3.5 प्रतिशत पर छोड़ा था।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के एक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2009–10 में कृषि क्षेत्र में 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि होगी तथा कुल अनाज उत्पादन 2009–10 में 2008–09 के 23 करोड़ 40 लाख टन से घटकर केवल 22 करोड़ 30 लाख टन रह जाएगा। इसी अवधि में तिलहन का उत्पादन 28 करोड़ टन से घटकर 27 करोड़ टन रह जाएगा। इसी रिपोर्ट में एक और भयानक तथ्य है कि 'थोक मूल्य सूचकांक' वर्ष 2009–10 में 13 प्रतिशत बढ़ा है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंदी का शिकार नहीं हुआ और इससे बहुत हद तक अछूता ही रहा है। फिर भी हमारे यहां महंगाई बढ़ गई है और आर्थिक विकास दर कम होती गई है। राजकोषीय घाटा तो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है।

आर्थिक विकास दर 2008–09 के प्रथम भाग के 7.7 प्रतिशत से घटकर दूसरे भाग में 5.8 प्रतिशत रह गई। पिछले वर्ष राजकोषीय घाटा 8.7 प्रतिशत रहा और अगर बजट से अलग मदों को जोड़ दें तो यह सकल घरेलू उत्पाद का 10.4 प्रतिशत हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहा अंतरराष्ट्रीय मंदी के दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के मूल्य घट रहे थे उसी समय हमारे यहा मूल्य बढ़ने लगे? उल्लेखनीय है कि राजग सरकार ने वर्ष 2003 में राजकोषीय घाटा और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया था, जिसके अंतर्गत राजकोषीय घाटे को 2008–09 तक 3 प्रतिशत और राजस्व घाटे को 2008 तक शून्य प्रतिशत के आकड़े पर लाने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री ने अब यह कहा है कि इस वर्ष ये दोनों आंकड़े 6.8 प्रतिशत एवं 4.8 प्रतिशत होंगे। इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है।

संप्रग सरकार ने आयल और उर्वरक बांड जारी कर बड़ी चतुराई से चाल चली है। राजग सरकार द्वारा समाप्त की गई एपीएम प्रणाली को भयावह तरीके से पिछले दरवाजे से बांड के रूप में सरकार ले आई है। इस हेराफेरी के द्वारा वह इन बांड को बजट में शामिल ही नहीं करती। यह कोई छोटा–मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले साल सरकार ने तेल के बांड पर करीब 75 हजार करोड़ रुपये और फर्टिलाइजर के बांड

***राजनीतिक वाहवाही लूटने के प्रयास ने संप्रग सरकार को वोट तो दिला दिए, लेकिन वह समय दूर नहीं जब देश के लोग देर–सबेर जान जाएंगे कि महंगाई का राज और कारण इस सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं।***

पर 1,17,000 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और इस रकम को अपने बहीखातों में दिखाया तक नहीं। अब यदि इस रकम को बजट में शामिल किया जाता है तो राजकोषीय और राजस्व घाटे का अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक ही रहता। इन घाटों का सीधा असर मूल्य वृद्धि पर पड़ता है। जब सरकार राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी और 2009–10 में 40000 करोड़ रुपये के आयल बांड देकर तेल कंपनियों को रियायत देगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही।

जब सरकार पेट्रोल मूल्य निर्धारण के लिए तीन वर्ष में तीन समितियां गठित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करेगी तो फर्टिलाइजर पर एक लाख करोड़ से अधिक के बांड पर व्यय करना ही पड़ेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में संप्रग सरकार ने 80 हजार मेगावाट विद्युत क्षमता बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन हम अभी तक इसके आधे स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। आज प्रति मेगावाट बिजली के संयंत्र स्थापित करने का व्यय लगभग चार करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। अर्थात् 80 हजार मेगावाट के लिए हमें करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये चाहिए।

अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को यदि बदले की भावना से रोका न गया होता तो आज लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही होती और करोड़ों रुपये आयल बांड पर बचाए जा सकते थे। स्पष्ट है कि इससे मूल्य वृद्धि पर भी रोक लगाई जा सकती थी, पर इस सरकार को न तो बिजली की चिंता है और न ही अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ सड़क की।

कृषि पर आज देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कुल 17 प्रतिशत है। सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रही है? राजनीतिक वाहवाही लूटने के प्रयास ने संप्रग सरकार को वोट तो दिला दिए, लेकिन वह समय दूर नहीं जब देश के लोग देर–सबेर जान जाएंगे कि महंगाई का राज और कारण इस सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं। ■

***(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)***

# बेलगाम महंगाई के मुद्दे पर कृषिमंत्री का राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ना अनुचित

केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने मूल्य वृद्धि का ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ते हुए कहा है कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी को नहीं रोक पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकारें इस मामले में सहयोग नहीं करती तो वर्तमान स्थिति का मुकाबला करना और भी कठिन हो जाएगा। गत 20 दिसम्बर को एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शरद पवार ने कहा कि गेहूं, चावल, चीनी और दालों की बेकाबू हो गई कीमतों के लिए वे जिम्मेदार नहीं है। महंगाई को लेकर भी पवार को लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी के भीतर सफाई देने को विवश होना पड़ा है। हालांकि उनकी दलील से पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं दिखे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी ने मुंह भी नहीं खोला।

पिछले दो सालों से शरद पवार आंकड़ों का पुलिंदा बांटकर पार्टी के भीतर इसी तरह से सफाई देते आए हैं। आंकड़ें बांटने का उनका मकसद यही रहता है कि इसके जरिए पार्टी के नेता महंगाई को लेकर सवाल करने वालों को करारा जवाब दे सकें। पिछले साल तो महंगाई को लेकर यूपीए सरकार के दो साझेदार कांग्रेस और एनसीपी के नेता ही आपस में ही भिड़ गए थे। एनसीपी की राजनीति शरद पवार के इर्द–गिर्द ही घूमती है। इसलिए पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है जो सीधे उनसे महंगाई पर जवाब तलब कर सके। लेकिन श्री पवार मानते हैं कि उनके कृषि मंत्री रहने पर महंगाई बढ़ने से पार्टी के नेता असहज महसूस करते हैं। इसीलिए वह पार्टी के भीतर महंगाई पर जवाब देने के लिए विवश होते हैं।

हालांकि उनके पास कहने के लिए नया कुछ नहीं होता है। महंगाई के लिए राज्यों में सूखा और बाढ़ का दुखड़ा उन्होंने हाल में संसद में मंगाई पर हुई चर्चा के दौरान भी रोया था। लेकिन यह बात उनकी पार्टी के भीतर भी किसी के गले नहीं उतर रही है कि अगर गेहूं और चावल का देश में पर्याप्त स्टॉक है तो इन दोनों के दाम क्यों इतने चढ़े हुए हैं? शक्कर के दाम एक साल में 16रूपए से बढ़कर 50 रूपए तक पहुंच जाने को लेकर भी एनसीपी के नेता शरद पवार का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। उड़द की दाल 60 फीसद और तुअर की दाल 72 फीसद महंगी होने की बात स्वयं उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री केवी थॉमस ने स्वीकार की है।

कौन बोल रहा है झूठ– एक तरफ कृषि मंत्री शरद पवार कह रहे हैं कि राज्य सरकारें जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही हैं। इधर राज्यों की रिपोर्ट है कि इस साल 131875 दुकानों पर छापा मारा गया है। छापे की कार्रवाई में राज्यों ने 6436 व्यक्तियों को पकड़ा है। यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिकनियम 1955 के तहत की गई है।

**यह है हकीकत**

- संसद की उपभोक्ता मामलों की समिति का कहना है कि शक्कर और दालों की कीमत छह महीने में दोगुनी हुई हैं। समिति के मुताबिक तुअर की दाल 100 रूपए किलो बिक रही है।
- इसी समिति का निष्कर्ष है कि शक्कर आयात करने के सरकारी फैसले में देरी ने बढ़ाए हैं इसके दाम। सरकार की बजाय व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में शक्कर मंगा ली है और अब वही इसकी 'बनावटी कमी' पैदा कर रहे हैं।
- कनाडा से पीली दाल के आयात पर भी इस समिति ने सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा है कि घाटे का सौदा क्यों किया गया।
- समिति ने यह भी कहा है कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय महंगाई को मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकता। उसे सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आवश्यक कदम उठाने ही होंगे। ■

# नीतियों की भूल-भुलैया

& Mk- ejyh eukgj tk'kh

Cka ग्लादेश में 3448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। भारत में 2915 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल होता है। फ्रांस में 7449 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है और भारत में 2770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हमारे यहां साल में तीन फसलें होती हैं। यहां की भूमि सबसे उर्वर है। फ्रांस में साल में केवल एक फसल होती है लेकिन इस मामले में उनकी स्थिति अच्छी है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी बार–बार दावा कर रहे हैं कि महंगाई जल्द ही दूर होगी और आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं होगा लेकिन चार नवंबर को उन्होंने जो भाषण दिया उसमें महंगाई के बारे में चिंता भी नहीं जताई गई है। रिजर्व बैंक विकास दर में बढ़ोतरी का दावा कर रहा है। कृषि मंत्री कहते हैं कि महंगाई पर काबू करना उनके हाथ में नहीं है। वह कहते हैं कि फसल का मामला राज्य सरकारों के हाथ में है। योजना आयोग ने कहा है कि वर्ष 2007–08 में दालों का उत्पादन और इसकी मांग एवं आपूर्ति में भारी अंतर रहा। वर्ष 2007–08 में दालों का उत्पादन 1.677 करोड़ टन, वर्ष 2008–09 में 1.751 करोड़ टन और वर्ष 2009–2010 में 1.829 करोड़ टन हुआ। वर्ष 2007–08 में दालों की मांग और आपूर्ति में 20.74 लाख टन, 2008–2009 में 30 लाख टन और वर्ष 2009–2010 में 30.28 लाख टन का अंतर है। इस स्थिति में दाल की खेती का रकबा बढ़ाना चाहिए था। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आमदनी बढ़ गई है इसलिए दालों का उपभोग बढ़ गया। लेकिन इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1960 में दाल की प्रति व्यक्ति खपत 27 किलोग्राम थी जो अभी 11 किलोग्राम है। आज हम दाल का आयात कर रहे हैं।

जिन देशों से हम दालों का आयात कर रहे हैं उन देशों को पता है कि हमारे यहां इसकी कमी होने वाली है। सरकार इन देशों को बता रही है कि एक साल तक महंगाई कम नहीं होगीए दालों का उत्पादन कम होगा और आप अपने यहां का स्टाक हमें बेचने के लिए तैयार रहो। हमारे देश और विदेश में उत्पादकता की तुलना के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बांग्लादेश में 3448 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। भारत में 2915 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल होता है। मिस्र में 9135 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। जापान में 6582 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। फ्रांस में 7449 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन होता है और भारत में 2770 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हमारे यहां साल में तीन–तीन फसलें होती हैं। यहां की भूमि सबसे उर्वर है। फ्रांस में साल में केवल एक फसल होती है लेकिन इस मामले में उनकी स्थिति अच्छी है। यहां तक कि इंग्लैंड में भी 8043 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदा होता है। फ्रांस में मक्का 8813 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिस्र में 7779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है जबकि भारत में केवल 1705 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। आप गन्ने का उत्पादन देखिए। मिस्र में 119893 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और भारत में 68049 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। हमसे ज्यादा कोलंबिया में 94779 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। चीन उत्पादन में हमसे बराबरी पर है। हम मूंगफली पैदा कर रहे हैं 794 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चीन पैदा कर रहा है 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। भारत में फसलों का उत्पादन बहुत कम है। यह आज से नहीं है। हर बार कहा जाता है कि हम कृषि में निवेश बढ़ा रहे हैं, कि हम उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार कैसे मुद्रास्फीति पर लगाम लगाएगी। मुझे लगता है कि जान–बूझकर देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जा रहा है। देश में अनाज की कमी बनाए रखने की नीति सरकार की है ताकि विदेश में रहने वाले आपके दोस्तों का खजाना भर सके। आप देश के लोगों को भूखा रखकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इस देश के गरीब आदमी का पैसा आप अमेरिका और कनाडा भेज रहे हैं। यह बहुत घातक नीति है।

***मुझे लगता है कि जान–बूझकर देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जा रहा है। देश में अनाज की कमी बनाए रखने की नीति सरकार की है ताकि विदेश में रहने वाले आपके दोस्तों का खजाना भर सके। आप देश के लोगों को भूखा रखकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। इस देश के गरीब आदमी का पैसा आप अमेरिका और कनाडा भेज रहे हैं। यह बहुत घातक नीति है।***

मोटे अनाज के बारे में सरकार की नीति समझ से परे है। मोटा अनाज हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी था। आज मोटे अनाज का उत्पादन घट गया है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दाल के बारे में यह देखकर आश्चर्य होता है कि किसान आज दाल का उत्पादन नहीं करना चाहते हैं। किसानों का तर्क है कि इसमें उन्हें नुकसान होता है। सरकार ने दालों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ है। दालों के लिए जो इंसेंटिव्स दिए हैंए वे काम नहीं कर रहे हैं। क्या सरकार ने कभी यह जानने का प्रयास किया कि उत्पादन क्यों घट रहा हैघ इसका कारण है सरकार की गलत मूल्य निर्धारण नीति। अनाज के मामले में सरकार की मूल्य निर्धारण नीति गलत है।

सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का

हिसाब–किताब भी मजेदार है। अगर आपसे मैं 10,000 हजार रुपए उधार लूं तो यह बढ़ती है और अगर आपको मैं 10,000 रुपया वापस कर दूं तो भी यह बढ़ती है। अगर दाम बढ़ जाए और उत्पादन न बढ़े तो भी यह बढ़ती है। यह क्या गोरखधंधा है? सरकार को यह देखना चाहिए कि आज हजारों करोड़ रुपए का वारा–न्यारा दालों और अनाज में कैसे हो रहा है।

वित्त मंत्री को यह बताना चाहिए कि अभाव पैदा कर सकल घरेलू उत्पाद क्यों बढ़ाया जा रहा है? चीनी के स्टॉक में कमी नहीं है। कमी वितरण प्रणाली में है। इस देश की 65 प्रतिशत चीनी पेप्सीकोलाए केंपाकोला और चॉकलेट एवं आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों के पास पहुंच जाती है। बाकी 35 प्रतिशत आम आदमी के लिए है। लेवी शुगर 10 प्रतिशत है। इसे 25 प्रतिशत क्यों नहीं किया जा रहा है?

सरकार को दो बातों पर गौर करना चाहिए। इस देश में भूख बढ़ रही है। सरकार के मंत्रियों को कुलदीप नैयर का एक लेख पड़ना चाहिए जो 5 दिसंबर को ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था। यह लेख सरकार की नीतियों के बारे में है। वह कहते हैं कि 27 अक्टूबर तक वह कुछ नहीं करने वाले थे। फिर नीति बनाएंगे, फिर उस पर अमल होगा। यह भी कहा जा रहा है कि भगवान जाने कब होगा! फिर वह आगे कह रहे हैं, अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति 2010 तक सात प्रतिशत तक चली जाएगी जिसे सरकार पांच प्रतिशत तक रखना चाहती थी। रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं, दूसरे बैंक कहते हैं और सरकार के आंकड़े हैं। यह चिंताजनक है सरकार मुद्रास्फीति पर कैसे नियंत्रण करेगी।

देश के लोगों को अभी दो साल और महंगाई की चक्की में पिसना पड़ेगा, यह सरकार की नीति है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार यह भी कहती है कि 27 दिसम्बर को इसकी समीक्षा की जाएगी और अगला आवश्यक कदम उठाया जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा।■

***(लेखक पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं।)***

# ममता ने खोली लालू के कैश सरप्लस की पोल

पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेलवे के कैश सरप्लस होने की पोल रेल मंत्री ममता बनर्जी ने खोल दी है। रेल मंत्री द्वारा संसद में रखे गए श्वेत पत्र के मुताबिक पिछले पांच सालों में रेलवे ने अकाउंटिंग नियमों में फेरबदल कर ज्यादा कैश सरप्लस दिखाया। पिछले पांच सालों में रेलवे ने माल ढुलाई में भारी बढ़ोतरी की है और घोषणा के विपरीत यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की। हालांकि रेल मंत्री ममता बनर्जी ने श्वेत पत्र में कहा कि उनकी मंशा सिर्फ आत्मविश्लेषण करने की है, कुछ और नहीं।

पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में 88,669 करोड़ रुपये के कैश सरप्लस की घोषणा की थी। लेकिन ममता के श्वेत पत्र में यह 17,006 करोड़ रुपये कम बताया गया है। पत्र के मुताबिक कैश सरप्लस गिनने की प्रक्रिया में बदलाव करने से यह बढ़ोतरी हुई है। लालू के कार्यकाल में छठे वेतन आयोग के भुगतानों की गणना नहीं की गई थी। अगर इनको गिना जाए तो कैश सरप्लस 62,363 करोड़ रुपये रह जाएगा। यही नहीं, अगर पुरानी अकाउंटिंग प्रेक्टिस को अपनाते हुए निवेश फंड के लिए रकम रखी जाए तो यह सरप्लस और कम 43,220 करोड़ रुपये रह जाएगा। यह लालू द्वारा दिखाए गए 88,669 करोड़ रुपये के आंकड़े के आधे से भी कम है।

श्वेत पत्र के मुताबिक पिछले दो दशकों में भारतीय रेल के लिए सर्वोत्तम साल पिछले पांच साल नहीं बल्कि पूर्व रेल मंत्री सी.के. जाफर शरीफ (1991–96) का कार्यकाल रहा था। पिछले पांच सालों में रेलवे ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपनी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी नहीं की है। यह 1.18 फीसदी के स्तर पर स्थिर रही है। हालांकि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए अपने पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते थे। पत्र के मुताबिक पिछले पांच सालों में रेल की पटरियों पर ज्यादा कमाई के चक्कर में बोझ बढ़ा दिया गया था। जिसका खमियाजा ज्यादा टूट–फूट से चुकाया जा रहा है।

लालू के कार्यकाल में मालभाड़े में भी भारी भरकम बढ़ोतरी की गई। इस दौरान खाने–पीने की वस्तुओं की ढुलाई 44 फीसदी महंगी हुई, जबकि उर्वरकों की ढुलाई 35 फीसदी बढ़ी। पत्र में माना गया है कि रेलवे टाइम टेबल के मामले में काफी पीछे रहा। पत्र में साफ कहा गया है कि पिछले पांच सालों में रेलवे में कायाकल्प करने की बात कहना ठीक नहीं है। बल्कि यह तो अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण हुआ है। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया है कि रेल यात्रियों को मूर्ख बनाया गया। मालभाड़े और किरायों में लगातार सरचार्ज लगाकर बढ़ोतरी की गई। लेकिन कहा गया कि बढ़ोतरी नहीं हुई है। पत्र में लालू की खानपान नीति को भी नहीं छोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच सालों में कुछ ऑपरेटरों ने खानपान के लाइसेंस इक्ट्ठा किए हैं। इसकी व्यापक समीक्षा जरूरी है। ■

# कांग्रेस सरकार सभी मोर्चे पर विफल

fnल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से 14 दिसम्बर को दिल्ली विधानसभा पर विशाल धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने किया। धरने में प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों, विधायकों, निगम पार्षदों, मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

धरने को प्रदेशाध्यक्ष के अतिरिक्त दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हर्ष वर्धन, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. नन्द किशोर गर्ग, श्रीमती विशाखा शैलानी, श्री पवन शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री रमेश बिधूड़ी, सरदार आर.पी. सिंह और श्री प्रवेश वर्मा, विधायक जगदीश मुखी, हरशरण सिंह बल्ली, करण सिंह तंवर, जिलाध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सरदार कुलदीप सिंह, मोर्चाध्यक्ष राज कुमार बल्लन, सरिता चौधरी, आतिफ रशीद, अनुज शर्मा, दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता श्री सुभाष आर्य ने सम्बोधित किया।

सभी वक्ताओं ने दिल्ली सरकार की चौतरफा असफलता का ज़िक्र किया और उसे आम आदमी पर भारी आर्थिक बोझ लादने का दोषी ठहराया। वक्ताओं ने दिल्ली सरकार की निम्नलिखित असफलताओं का जिक्र किया।

1. बेहताशा मंहगाई : आम आदमी की जरूरत की सभी वस्तुओं की दरों में शीला दीक्षित सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में बेहताशा वृद्धि हुई है। चाहे अनाज हो या फिर दालें, चीनी, सब्जी, तेल और दूध। पानी–बिजली जैसी नागरिक सुविधाएं मंहगी कर दी गई हैं। सार्वजनिक परिवहन डीटीसी और मैट्रो के किरायों में भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे पूर्व स्कूलों की फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर भारी बोझ लादा गया था।
2. अनधिकृत बस्तियों के निवासियों से विश्वासघात : एक वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के मौके पर दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने अनधिकृत बस्तियों के नियमितीकरण का विश्वास दिलाया था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किए थे। लेकिन एक वर्ष पूरा होने के बाद भी इन बस्तियों का नियमितीकरण नहीं किया गया। इन बस्तियों के लोग अपने को छला हुआ अनुभव कर रहे हैं।
3. चरमराती कानून व्यवस्था : एक के बाद एक वक्ताओं ने दिल्ली की मौजूदा कानून व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से अफजल की फाइल को दबाए रखने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की गई। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई।
4. सरकारी स्कूलों की शोचनीय दशाः वक्ताओं ने हाल ही में गठित खजूरीखास के सरकारी स्कूल में हुई कुछ बच्चों की मौत और त्रिलोक पुरी के स्कूल में मिड–डे मील के कारण सौ से अधिक बच्चों के बीमार पड़ जाने का हवाला देते हुए सरकारी स्कूलों की प्रबंध व्यवस्था पर और सुविधाओं के नित्तांत अभाव पर गहरी चिंता व्यक्त की और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिए जाने की मांग की।
5. लो–फ्लोर बसें : दिल्ली सरकार ने मंहगी लो–लो बसें दिल्ली की सड़कों पर उतार कर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। इन बसों से कहीं कम दाम पर साधारण बसें बड़ी संख्या में खरीद कर दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाया जा सकता था। लो–लोर बसों में पिछले दो सप्ताह में आग लगने जैसे घटनाएं हो चुकी हैं। इन बसों की तकनीकी खामियों और रखरखाव की सही व्यवस्था न होने के कारण आज आम नागरिक इन बसों में अपने को सफल करने में असुरक्षित महसूस कर रहा है।
6. अपनी छवि बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विज्ञापनों पर भारी खर्च : दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता के धन का सरकारी विज्ञापनों पर अनाप–शनाप खर्च कर रही हैं। एक ओर तो घाटे की दुहाई देकर बिजली–पानी की दरें बढ़ाई जाती हैं और दूसरी ओर जनता के धन का विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर अनियंत्रित खर्च किया जाता है। यही नहीं राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में विलम्ब और इनसे जुड़े प्रोजेक्टों के समय पर पूरा न होने से इनकी लागत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका बोझ भी आम नागरिक पर ही अन्ततः पड़ रहा है।

दिल्ली की कांग्रेस सरकार को तीसरी बार सत्ता में आए अभी एक वर्ष हुआ है। इस एक वर्ष के दौरान सभी मोर्चों पर इसका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और आज दिल्लीवासी आर्थिक बोझ, असुरक्षा और छले जाने की पीड़ा को झेल रहा है। ■

# म.प्र. निकाय चुनाव में भाजपा का परचम

नगरीय निकाय चुनाव परिणाम के पहले दौर में मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 7 नगर निगमों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस के खाते में देवास और कटनी तथा बसपा के खाते में सतना और सिंगरौली नगर निगम गए हैं जबकि सागर नगर निगम पर किन्नर प्रत्याशी की जीत हुई है।

इंदौर में लगातार तीसरी बार भाजपा की परिषद बनने जा रही है। यहाँ 69 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 46, कांग्रेस ने 19 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 सीटें जीती हैं। इंदौर की प्रतिष्ठापूर्ण महापौर की सीट पर कृष्ण मुरारी मोघे काबिज हुए हैं। आधी रात को रद्द किए गए मतों की पुनः गणना के पश्चात भाजपा के मोघे ने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज संघवी को 3 हजार 292 मतों से पराजित किया। मोघे को 3 लाख 18 हजार 410 और संघवी को 3 लाख 15 हजार 118 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी ने 22 हजार से ज्यादा निरस्त किए गए मतों की दोबारा से गणना करने की माँग की थी, लेकिन इस गणना में भी संघवी की नैया पार नहीं लग सकी।

मध्यप्रदेश के चार प्रमुख नगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भाजपा के महापौर चुने गए हैं। इनमें से तीन निगम पहले भी उसके पास थे और भोपाल की सीट उसने कांग्रेस से छीनी है। सबसे चौंकाने वाला परिणाम सागर का रहा जहाँ भाजपा व कांग्रेस दोनों को पछाड़ते हुए किन्नर प्रत्याशी कमला बुआ ने जीत दर्ज की।

मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के 7 महापौर, कांग्रेस बसपा के खाते में दो–दो, सागर में निर्दलीय किन्नर का कमाल, सत्तारूढ़ दल को पांच का नुकसान। इंदौर में भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे ने कांग्रेस के पंकज संघवी को शिकस्त दीनगर पालिका चुनावों में भी भाजपा को आधे निकायों पर ही संतोष करना पड़ रहा है। लेकिन नगर पंचायतों में उसे कांग्रेस पर बढ़त हासिल हुई है। रतलाम नगर निगम सहित शेष 146 नगरीय निकायों के लिए मतगणना 17 दिसंबर को होगी।

भाजपा को इस बार पांच निगमों का घाटा हुआ है। जबकि बसपा ने अपनी ताकत में इजाफा करते हुए विंध्य क्षेत्र के दो निगम सतना और सिंगरौली अपनी झोली में डाल लिए हैं। राज्य में कुल 14 नगर निगम हैं, इनमें से उज्जैन निगम का कार्यकाल शेष रहने के कारण चुनाव 13 निगमों में ही हुए हैं।

पिछली बार 14 में से 10 निगमों में भाजपा जीती थी और दो पर कांग्रेस। दो अन्य निगम निर्दलियों के कब्जे में गए थे। बाद में उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था और इस तरह भाजपा के प्रभाव वाले नगर निगमों की संख्या 12 हो गई थी। देर रात तक चल रही मतगणना के नतीजों और रुझानों के मुताबिक भोपाल में कांग्रेस के 70 में से 48 पार्षद चुनाव जीते हैं। भोपाल मे पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर ने जीत दर्ज कराई है तो खंडवा में आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की पत्नी भावना शाह महापौर बनी हैं।

15 दिसम्बर को जिन 41 नगर पालिकाओं के लिए मतगणना हुई, उनमें से 19 में भाजपा और 17 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। दो निर्दलियों के अलावा सपाएसीपीएम व बसपा के खाते में एक एक नगर पालिका गई है। 69 नगर पंचायतों में से 68 के नतीजे घोषित हुए हैं। इनमें से 32 पर भाजपा 20 पर कांग्रेस और 13 पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। दो बीएसपी और एक सपा के खाते में गई हैं।

15 दिसम्बर को 12 नगर निगमों, 41 नगर पालिकाओं और 69 नगर पंचायतों सहित 122 निकायों के लिए मतगणना हुई। चन्दला नगर पंचायत में मतगणना के दौरान बवाल होने से काम रोक दिया गया। ज्यादातर जगहों पर महापौर चुनाव के परिणाम चक्रवार घोषित करने में विलंब हुआ।

विवाद की स्थिति भी बनी। कटनी में विजयराघवगढ़ से कांग्रेस के विधायक संजय पाठक के विरोध के बाद पहले चरण के परिणाम घोषित किए गए। भोपाल में रात सवा बारह बजे रात तक तीन चरण के नतीजे ही घोषित किए जा सके। इंदौर में अंतिम दौर में कांग्रेस की आपत्ति के बाद देर रात निरस्त हुए 30 हजार से अधिक मतों की पुनर्गणना कराई गई। सिंगरौली में भी बसपा उम्मीदवार के 1300 मतों से आगे होने पर भाजपा ने पुनर्गणना की मांग की ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिणाम नगरीकरण की बुराइयों के खिलाफ हमारे द्वारा शुरू किए गए अभियान में जनता के विश्वास की विजय हैं। हम आगे और भी उत्साह से मध्यप्रदेश के शहरों की बेहतरी के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। ■

*कर्नाटक*

## विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 10 स्थानों पर जीत दर्ज की

गत 21 दिसम्बर को कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन ने क्रमशः 10 और 5 सीटों पर जीत हासिल की। 10 सीटें जीतने के बाद विधानसभा के ऊपरी सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या 34 हो गई है। भाजपा ने अपनी चार पुरानी सीटें बरकरार रखी है और छह नई सीटें जीती है। इस चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस अपनी पुरानी 19 सीटों में से मात्र 10 सीटें ही जीत पाई है। चुनाव 23 सीटों के लिए हुआ, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने एक–एक सीटें निर्विरोध हासिल कर ली थी। ■

# एक और हजार का फर्क

## &Mk- onçrki ofnd

Hkkरत में गरीब होने का अर्थ जैसा है, वैसा शायद दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में जिसकी आय 20 से कम है, सिर्फ वही गरीब हैं बाकी सब? यदि सरकार और हमारे अर्थशास्त्रियों की मानें तो बाकी सब अमीर हैं 25 रोज़ से 25 लाख रू. रोज तक कमानेवाले सभी एक श्रेणी में हैं इससे बड़ा मज़ाक क्या हो सकता है? ये लोग गरीबी की रेखा के उपर हैं जो नीचे हैं, उनकी संख्या भी तेंदुलकर–कमेटी के अनुसार 37 करोड़ 20 लाख है। ये 37 करोड़ लोग, हम ज़रा सोचें, 20 रोज़ में क्या–क्या कर सकते हैं? अगर कोई इन्सान इन्सान की तरह नहीं, जानवर की तरह भी रहना चाहे तो उसे कम से कम क्या–क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। बीमार पड़ने पर दवा भी चाहिए। और अगर मिल सके तो अपने बच्चों के लिए शिक्षा भी चाहिए। क्या 20 रोज में आज कोई व्यक्ति अपना पेट भी भर सकता है? आजकल गाय और भैंस 20 से ज्यादा की घास खा जाती हैं क्या हमें पता है कि देश के करोड़ों वनवासी ऐसे भी हैं, जिन्हें गेहूं और चावल भी नसीब नहीं होता। इस देश के जानवर शायद भरपेट खाते हों लेकिन इन्सान तो भूखे ही सोते हैं। वे इसलिए भी भूखे सोते हैं कि वे इन्सान हैं, वे एक–दूसरे का भोजन छीनते–छपटते नहीं। गरीब परिवारों में कभी बाप भूखा सोता है तो कभी मां और कभी–कभी बच्चों को भी अपने पेट पर पट्टी बांधनी होती हैं। जहां तक कपड़ों और मकान का सवाल है, भोजन के मुकाबले उनका महत्व नगण्य हैं किसी तरह तन ढक जाए और रात को लेटने की जगह मिल जाए, इतना काफी हैं। ऐसे 37 करोड़ लोगों का देश दुनिया में कोई और नहीं हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं रहते हैं तो भारत में ही रहते हैं।

यह तो सरकारी आंकड़ा है लेकिन असलियत क्या है? असलियत का अंदाज तो सेनगुप्ता–कमेटी की रपट से मिलता हैं। उसके अनुसार भारत के लगभग 80 करोड़ लोग 20 रू. रोज़ पर गुजारा करते हैं यहां तेंदुलकर–रपट सिर के बल खड़ी हैं। किसे सही माना जाए? तेंदुलकर को या सेनगुप्ता को? भारत का तथाकथित मध्यम–वर्ग यदि 25–30 करोड़ लोगों का है तो शेष 80 करोड़ लोग आखिर किस वर्ग में होंगे? उन्हें निम्न या निम्न–मध्यम वर्ग ही तो कहेंगे, उनकी दशा क्या है? क्या वे इंसानों की जिंदगी जी रहे हैं? उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हैं, वे गरीबी नहीं, गुलामी का जीवन जी रहे हैं, वे लोग कौन हैं?

ये वे लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, पिछड़ी और अस्पृश्य जातियों के हैं, शहरों में मजदूरी करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हैं और जिन्हें सिर्फ पेट भरने, तन ढकने और सोने की सुविधा हैं। इन्हें वोट का अधिकार तो है लेकिन पेट का अधिकार नहीं हैं। यह भारत हैं, यह भूखा और नंगा है और वह इंडिया हैं उसमें वही 25–30 करोड़ लोग रहते हैं, ये नागरिक हैं, सभ्य हैं, स्वामी हैं कौन हैं, ये लोग? ये शहरी हैं, ऊंची जातियों के हैं, अंग्रेजीदां हैं, राजनीति, व्यापार और ऊंची नौकरियों पर इन्हीं का कब्जा है, इन्हीं के लिए चिकनी–चिकनी सड़कें, रेल, हवाई जहाज, कारें बनती हैं, बड़े–बड़े स्कूल, अस्पताल और कालोनियां खड़ी की जाती हैं। इनका संसार अपना है और अलग हैं। यही वर्ग तय करता है कि गरीबी क्या है और गरीबी कैसे हटाई जाए? इसीलिए यह फतवा जारी कर देता है कि जो 20रू. से ज्यादा कमाता है, वह गरीब नहीं है और जो गरीब नहीं है, वह चिल्लाए क्यों और उसके लिए कुछ खास क्यों किया जाए? याने देश के 80 करोड़ लोगों के बारे में विशेष चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग गरीबी की रेखा के ऊपर हैं। जिन 37 करोड़ लोगों की चिंता है, उनकी गरीबी दूर करने के प्रयास जरूर होते हैं लेकिन वे सतही और तात्कालिक होते हैं और उनमें से ज्यादातर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाते हैं। सस्ते राशन और 'नरेगा' (ग्रामीण रोजगार) से क्या वाकई गरीबी हटाई जा सकती है? ये काम भी यदि ईमानदारी से किए जाएं तो थोड़ी देर के लिए गरीबी हटती जरूर है लेकिन वह मिटती बिल्कुल भी नहीं। उसकी जड़ पर प्रहार होना तो बहुत दूर की बात हैं सरकारी प्रयास तो उसकी जड़ को छूते तक नहीं।

हमारी सरकारों ने गरीबी की जड़ उखाड़ने की बात कभी सोची ही नहीं। हजारों बरस से चली आ रही हमारी

***क्या 20 रोज में आज कोई व्यक्ति अपना पेट भी भर सकता है? आजकल गाय और भैंस 20 से ज्यादा की घास खा जाती हैं क्या हमें पता है कि देश के करोड़ों वनवासी ऐसे भी हैं, जिन्हें गेहूं और चावल भी नसीब नहीं होता। इस देश के जानवर शायद भरपेट खाते हों लेकिन इन्सान तो भूखे ही सोते हैं।***

***ये वे लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, पिछड़ी और अस्पृश्य जातियों के हैं, शहरों में मजदूरी करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा से वंचित हैं और जिन्हें सिर्फ पेट भरने, तन ढकने और सोने की सुविधा हैं। इन्हें वोट का अधिकार तो है लेकिन पेट का अधिकार नहीं हैं।***

गरीबी का मूल कारण जातिवाद है। कुछ जातियां दिमाग का काम करेंगी और कुछ हांथ–पांव का ! दिमागवाली जातियां जूठन! इस तिकड़म को बरकरार रखने के लिए हमने सूत्र यह चलाया कि दिमागी काम की क़ीमत ज्यादा और शारीरिक काम की क़ीमत कम! कुर्सीतोड़ काम महत्वपूर्ण और हाथ–तोड़ काम महत्वहीन! ऊंची जातियां, शहरी लोगों और अंग्रेजीदानों ने कुर्सीतोड़ काम पकड लिए और ग्रामीणों, पिछड़ी जातियों और गरीबों ने हाड़–तोड़ काम ! यहीं इंडिया और भारत की खाई खड़ी हो गई। यह खाई तभी पटेगी, जब दिमागी और जिस्मानी कामों में चला आ रहा जमीन–आसमान का अंतर खत्म होगा। आज तो एक और हजारों का अंतर हैं। मजदूर को 100रू. रोज मिलते हैं तो कंपनी बॉस को लाखों रू. रोज़! यह अंतर एक और 10 का करने की हिम्मत जिस सरकार की होगी, वह गरीबी की जड़ पर पहला प्रहार करेगीं इसी प्रकार देश में दो प्रकार की शिक्षा और दो प्रकार की चिकित्सा का तुरंत खात्मा होना चाहिए। यदि अंग्रेजी की अनिवार्यता नौकरियों और शिक्षा से एक दम हट जाए तो गरीबों के बच्चों को अपना जौहर दिखाने का सच्चा मौका मिलेगा। आरक्षण, बेगारी भत्ता (ग्रामीण रोजगार), सस्ता अनाज आदि की अपमानजनक मेहरबानियां अपने आप अनावश्यक हो जाएंगी, अगर शिक्षा के बंद दरवाजे खोल दिए जाऐं किताबें रटाने की बजाय बच्चों को काम–धंधे सिखाए जाएं, छोटे–छोटे कर्जे देकर काम–धंधे खुलवाएं जाएं और अमीरों और नेताओं के अंधाधुंध खर्चों पर रोक लगाई जाए तो गरीबी कितने दिन टिकेगी ? हमारी सरकारें आमदनी पर तो टैक्स लगाती है, लेकिन खर्चों पर कोई सीधा टैक्स नहीं हैं। इसकी वजह से समाज में जबर्दस्त प्रतिस्पर्द्धा और भोगवाद को बढ़ावा मिलता हैं। लोग बचत करने की बजाय भ्रष्टाचार करने पर उतारू हो जाते हैं। यदि खर्च की सीमा बांधी जाए तो सामाजिक विषमता अपने आप घटेगी। गरीब को गरीबी उतनी नहीं चुभेगी। गरीबी अपने आप में ही अभिशाप हैं, जब तक उसे दूर नहीं किया जाता, लोकतंत्र और आर्थिक प्रगति कोरे दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ■

# अटलजी का 86 वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 86 वें जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसम्बर को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। डॉ. मनमोहन सिंह .ष्ण मेनन मार्ग स्थित श्री वाजपेयी के आवास पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने स्वयं पहुंचे। भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी वाजपेयी को शुभकामनाएं देने उनके आवास पहुंचे।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में 25 दिसंबर, 1924 को हुआ था।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटील की ओर से उनके प्रतिनिधि ने श्री वाजपेयी को गुलदस्ता और शुभकामना संदेश भेंट किया। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी, पार्टी के नवनियुक्त श्री अध्यक्ष नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री वीएस येदुयरप्पा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी तथा वरिष्ठ भाजपा नेता श्री वैंकेया नायडू, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री वाजपेयी को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सहकार्यवाह सुरेश सोनी ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामना दी। हिंदी फ़िल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी फ़ोन पर पूर्व प्रधानमंत्री को शुभकामना प्रेषित की। इस अवसर पर भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शाम को लोक अभियान की ओर से राजधानी में अनूप जलोटा के भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भाजपा के मुख्यालय में श्री वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में 86 किलोग्राम वजन के लड्डु का भगवान को भोग लगाया गया और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें 200 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया. श्री गडकरी ने 101 गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दान की।

उधर, उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने गरीबों में भोजन बांटकर वाजपेयी की लंबी उम्र की कामना के लिए मंदिरों में प्रार्थनाएं कीं। लखनऊ मे भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न अस्पतालों और गरीबों के पास जाकर खिचडी और फल वितरित किए। अपने नेता की दीर्घायु के लिए भाजपा नेताओं द्वारा लखनऊ के विभिन्न मंदिरों में रामायण के सुंदर कांड का पाठ और हवन किया जा रहा है। ■

# मुसलमानों को १० फीसदी आरक्षण की सिफारिश
# रंगनाथ आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश

मुसलमानों को आरक्षण तथा ईसाई और मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की विवादास्पद रिपोर्ट 18 दिसम्बर को लोकसभा में पेश की गई। अल्पसंख्यक मामलों एवं निगमित मामलों के राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद ने तेलंगाना मुद्दे पर चल रहे हंगामे के बीच यह रपट निचले सदन में पेश की।

मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण देने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमान सरकारी रोजगार में बहुत ही कम हैं और कभी–कभी बिलकुल ही नहीं हैं इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद–16 (4) विशेष रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक शब्दों के साथ 'पिछड़ा शब्द' की शर्त का उल्लेख किए बिना पिछड़ा माना जाना चाहिए और केन्द्र और राज्य सरकारों के अधीन सभी संवर्गों और ग्रेडों में पदों का 15 प्रतिशत उनके लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। आयोग ने कहा कि 15 प्रतिशत में से दस प्रतिशत सीटें मुसलमानों के लिए होंगी और शेष पाँच प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होंगी।

ईसाई और मुस्लिम दलितों को अनूसूचित जाति का दर्जा देने के बारे में आयोग ने कहा कि हम यह सिफारिश करते हैं कि अल्पसंख्यकों में उन सभी सामाजिक एवं व्यावसायिक समूहों को, यदि उनकी धार्मिक पहचान आड़े नहीं आती, अनुसूचित जाति की वर्तमान परिधि में शामिल किया जाता तो निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाना चाहिए चाहे उन अन्य समुदायों का धर्म जातिगत व्यवस्था को मान्यता देता हो या नहीं देता हो।

रिपोर्ट में कहा गया कि आयोग की इन सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनमें से प्रत्येक वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई के द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित हो सकती है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता वाले धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रपट को सच्चर समिति की रिपोर्ट के बाद के कदम के रूप में देखा जा रहा है। सच्चर समिति ने अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के पिछड़ेपन का विश्लेषण करते हुए अपनी रपट पेश की थी। मिश्रा आयोग ने मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के कई उपाय सुझाए हैं। आयोग की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों को नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है।

आयोग ने मई 2007 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रपट पेश कर दी थी और गैर भाजपाई विपक्ष की ओर से लगातार इस रपट को संसद में पेश करने और इसकी सिफारिशें लागू करने की माँग की जा रही थी। गैर भाजपाई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने यह माँग भी की कि सरकार को मिश्र आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई रपट भी पेश करनी चाहिए। खुर्शीद ने हालाँकि स्पष्ट किया कि कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है क्योंकि रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन जाँच आयोग कानून के तहत नहीं किया गया था। आयोग के कामकाज के दायरे में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक, सामाजिक रूप से अशक्त एवं पिछड़े वर्गों की पहचान कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण सहित विभिन्न कल्याणकारी उपाय सुझाना शामिल था। आयोग ने अपनी रपट में कहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पिछड़ेपन की पहचान के मामले में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ■

## रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट पर मुश्किल में फंसा केन्द्र

अल्पसंख्यकों के आरक्षण की सिफारिश करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश तो हो गई है लेकिन उसकी राह बहुत मुश्किल है। बल्कि कहा जा सकता है कि कुछ मायनों में सरकार दो पार्टी के बीच फंस गई है। सरकार की दुविधा यह है कि वह अल्पसंख्यकों को खुश करे या दलितों और पिछड़ों को या फिर सबको खुश कर सामान्य वर्ग की नाराजगी झेले।

कुल मिलाकर रिपोर्ट ने ऐसे विवादों का पिटारा खोल दिया है जहां राजनीति ज्यादा होगी, काम कम।

ऐसे में अल्पसंख्यकों के समर्थन के सहारे दोबारा केन्द्र में पहुंची कांग्रेस सरकार को रंगनाथ मिश्र रिपोर्ट ने असमंजस में डाल दिया है। रिपोर्ट की सिफारिशें मानने पर अल्पसंख्यकों के लिए न सिर्फ नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण का दरवाजा खोलना होगा बल्कि संसद और विधानसभाओं में भी उनको आरक्षण देना होगा। इतना ही नहीं परोक्ष रूप से महिला आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा की बात भी माननी होगी। आरक्षण का कोटा 50 प्रतिशत से कम रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल सरकार केवल वर्तमान आरक्षण के दायरे में ही फेरबदल कर सकती है। रिपोर्ट मे ओबीसी कोटा में ही अल्पसंख्यकों के लिए लगभग आठ प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश है। सरकार इस सिफारिश को माने तो ओबीसी की नाराजगी झेलने के लिए तैयार होना होगा। इसके लिए कांग्रेस के अंदर भी समर्थन नहीं है।

ओबीसी मान भी जाएं तो इसका असर महिला आरक्षण पर भी पड़ेगा। सपा, राजद, जनता दल(यू) जैसे कई दल महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग करते रहे हैं। ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होते ही इन दलों का दबाव बढ़ेगा। जबकि 1950 के प्रेसिडेंशियल आदेश के खत्म होते ही अल्पसंख्यक दलितों के लिए न सिर्फ शिक्षा और नौकरियों में बल्कि संसद में आरक्षित सीट के लिए भी राह खुल जाएगी। जाहिर है कि आरक्षित सीट से आने वाले वर्गों की ओर से इसका पुख्ता विरोध होगा। ■

# आरक्षण की धूर्त बिल्ली फिर थैले से बाहर

**fQjkt c[r vgen**

Hkkरत के मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा आए दिन उठाया जाता रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री सलमान खुर्शीद ने हाल में एक टीवी चैनल से बात करते हुए घोषणा की है कि छह महीने के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। यह कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों को इस तरह बहलाने और उन्हें रिझा कर अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अक्सर ही उन्हें ऐसे सब्जबाग दिखाए जाते हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में मुसलमानों को हमारे देश में सबसे पिछड़ी हुई कौम माना जाता है। इस पर विडंबना यह है कि मुस्लिमों के ज्यादातर नेता इस कोशिश में लगे दिखाई देते हैं कि किस तरह उनकी कौम को आरक्षण मिले, जबकि खुद मुसलमानों को इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है।

वैसे तो फिलहाल आरक्षण का जो धर्म और जाति पर आधारित ढांचा है वह पूरा का पूरा निरर्थक लगता है। यदि आरक्षण देना है तो हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि का अंतर खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण सिर्फ गरीबों को दिया जाना चाहिए, भले ही वे किसी भी धर्म और मत के क्यों न हों।

यह हमारे मुस्लिम समुदाय की विडंबना है कि उसके जो नेता आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, वे अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे कि वे असल में क्या कर रहे हैं? ये वही लोग हैं कि जो मंत्रालयों में हैं और ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी पिछड़ी कौम के भले का कोई काम नहीं किया है। हमारे ये नेतागण अपनी कौम का भला देखने की बजाय पहले अपना भला देखते हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज की तरक्की होना एक असंभव बात है। महात्मा गांधी ने 'हरिजन' के 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा कि धर्म के आधार पर दलित समाज को आरक्षण देना अनुचित होगा। आरक्षण का धर्म से कुछ लेना–देना नहीं है और सरकारी मदद केवल उसी को मिलनी चाहिए कि जो सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ हो। इसी तरह 26 मई 1949 को जब पंडित जवाहर लाल नेहरू कांस्टिटवेंट असेंबली में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जोर देकर कहा था कि यदि हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग को आरक्षण देंगे तो उससे समाज का संतुलन बिगड़ेगा। ऐसा आरक्षण देने से भाई–भाई के बीच दरार पैदा हो जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर बनी कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर 22 दिसंबर, 1949 को जब धारा 292 और 294 के तहत मतदान कराया गया था तो उस वक्त सात में से पांच वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। मौलाना आजाद, मौलाना हिज–उर–रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन और हुसैनभाई लालजी ने आरक्षण के विरोध में वोट डाला था। रोचक बात यह है कि उस समय सरदार पटेल ने आरक्षण के पक्ष में वोट डाला।

नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का और चाहे जो हाल हुआ हो, पर इसका एक स्पष्ट असर यह पड़ा कि इसके चलते समाज के समान रूप से विकास का मकसद खत्म हो गया। और तो और अब तो रिजर्व सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार तक नहीं मिलते हैं। रिजर्व सीटें सालों–साल से खाली रहती चली आई हैं। इससे न केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है, बल्कि सरकारी क्षेत्रों में काम की भी हानि हुई है। 1993 में आईआईटी, मद्रास के निदेशक पी. वी. इंदिरेशन और आईआईटी, दिल्ली के निदेशक एन. सी. निगम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की पचास फीसदी सीटें आईआईटी में खाली रह जाती हैं।

मुसलमानों को अगर आरक्षण मिलता है, तो इससे एक बड़ा नुकसान यह हो जाएगा कि जो थोड़े–बहुत मुसलमान आज अपने बल पर मुख्यधारा में कहीं–कहीं मौजूद दिखते हैं, आरक्षण मिलने की स्थिति में वे मेहनत करना छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी जिन गैर–मुस्लिम संस्थाओं में कुछ दरवाजे मुसलमानों के लिए खुले हुए हैं, खतरा है कि आगे चलकर उन्हें बंद न कर दिया जाए। आरक्षण दिए जाने की स्थिति में वहां मुसलमानों से कहा जा

***वैसे तो फिलहाल आरक्षण का जो धर्म और जाति पर आधारित ढांचा है वह पूरा का पूरा निरर्थक लगता है। यदि आरक्षण देना है तो हिंदू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, जैन आदि का अंतर खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण सिर्फ गरीबों को दिया जाना चाहिए, भले ही वे किसी भी धर्म और मत के क्यों न हों।***

***अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनकी हालत में कोई तब्दीली हो, तो इसके लिए उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। उन्हें आधुनिक शिक्षा हासिल करनी होगी और अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आरक्षण की बैसाखी उन्हें बहुत आगे नहीं ले जा सकती।***

सकता है कि बेहतर होगा कि वे वहां जाएं, जहां उन्हें आरक्षण हासिल है।

आरक्षण की बात उठाने वाले यह क्यों नहीं देख पाते कि डॉ. जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, ज्ञानी जैल सिंह या यहूदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजराइली आरक्षण की बैसाखी के बिना ही महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे और अपनी काबिलियत साबित की। सर सैयद अहमद खां ने 10 जनवरी, 1884 को मुल्तान में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना का उनका मकसद मुसलमानों को कठमुल्लेपन से छुटकारा दिलाते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। उनका मत था कि अंग्रेजी में तालीम नहीं मिल पाने के मुसलमान हिंदुओं से सौ साल पीछे चल रहे हैं। देश का गैर मुस्लिम तबका इसलिए ज्यादा तरक्की कर पाया क्योंकि उसने अंग्रेजी शिक्षा की अहमियत को समझ लिया था।

और फिर फर्ज कीजिए कि मुसलमानों को देश में आरक्षण दे दिया गया, तो क्या वे उसका सच में कोई फायदा उठा पाएंगे? लगता तो ऐसा है कि आरक्षण मिलने की सूरत में खुद मुसलमानों में कलह पैदा हो जाएगी क्योंकि यह समुदाय सैकड़ों जातियों में बंटा हुआ है। समस्या यह पैदा होगी कि निचले तबकों के मुसलमान ऊंची जाति के मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे, जबकि ऊंची जाति वाले मुसलमान खुद को अल्पसंख्यक तबका बताते हुए आरक्षण की पूरी मलाई सटकना चाहेंगे। मुसलमानों में सैयद, शेख, मुगल, पठान, राजपूत, ठाकुर, चौधरी, जाट आदि उच्च श्रेणी में आते हैं और जुलाहे, दर्जी, कुंजड़े, मनिहार, कसाब, कलाल, घोसी, नाई, सक्का, माहीगीर, बंजारा, हलाल खोर आदि हैं, जो पिछड़ी और निचली जातियों में शुमार किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के हाथ में आरक्षण का झुनझुना थमाने वाली सरकार को मुस्लिम समाज में पैदा होने वाली कलह से भी निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

अगर मुसलमान चाहते हैं कि उनकी हालत में कोई तब्दीली हो, तो इसके लिए उन्हें खुद आगे बढ़ना होगा। उन्हें आधुनिक शिक्षा हासिल करनी होगी और अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आरक्षण की बैसाखी उन्हें बहुत आगे नहीं ले जा सकती। *(साभार)* ■

# असलियत बयां कर रहे हैं गरीबी के नए आंकड़े

देश का हर तीसरा नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। प्रख्यात अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य सुरेश तेंदुलकर के नेतृत्व वाले विशेषज्ञ समूह का यही आंकलन है। ताजा आकलन में वर्ष 2004–2005 में देश में गरीबी 37.2 फीसदी आंकी गई है। नए आंकलन में ग्रामीण क्षेत्र में 41.8 गरीबी दर्ज की गई है जबकि शहरी क्षेत्र में यह 25.7 फीसदी है। पुराने आकलन में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी 28.5 और शहरी क्षेत्र में 25.7 फीसदी है। पहले गरीबी के आंकलन के लिए कैलोरी के उपभोग को आधार बनाया गया था, जबकि नए मानदंडों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर व्यक्ति के खर्च करने की क्षमता को मानक बनाया गया। यही कारण है कि पहले की तुलना में ज्यादा लोग गरीबी के दायरे में हैं।

बहरहाल, देश में जो हालात हैं, उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का पता लगाने के लिए शायद ही किसी आकलन की जरूरत थी। वर्ष 1991 में अर्थव्यवस्था में लागू किए गए सुधारों से देश की जीडीपी में लगातार सुधार हुआ। हम हिंदू विकास दर से आगे निकल कर नौ फीसदी तक विकास दर हासिल कर सके। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी का लाभ एक विस्तृत दायरे में नहीं पहुंच पाया। नॉलेज इकोनोमी के विकास और सर्विस सेक्टर के महान उदय का लाभ सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिल सका। यह लाभ उन्हीं को मिला जो सामाजिक विकास की दौड़ में आगे थे। हमारी नीति–निर्माताओं की एक बड़ी खामी यह रही कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन और सर्विस सेक्टर पर ध्यान देते वक्त कृषि क्षेत्र को तवज्जो देना बंद कर दिया गया। देश की ज्यादातर आबादी कृषि और कृषि से जुड़े रोजगारों पर आधारित है। लेकिन पिछले सत्रह–अठारह साल में इस क्षेत्र में कोई बड़ी परियोजना नहीं लाई गई। नतीजा सबके सामने है। देश में दालों और तिलहनों का उत्पादन ठहरा हुआ है। गेहूं और धान की पैदावार में भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। सप्लाई की कमी और बेलगाम बिचौलियों की वजह से खाने–पीने की चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं।

जाहिर है कृषि उत्पादकता में कमी और खेती–किसानी की बदहाली का असर ग्रामीण इलाके में बढ़ा है और वहां गरीबी में इजाफा हुआ है। इसी तरह देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जिस अनुपात में सार्वजनिक व्यय होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसका असर शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों जगहों पर मौजूद गरीबी पर पड़ा है। शहरी गरीबी एक बड़ा रूप ले रही है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इसकी भयावहता को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इन हालातों से साफ है कि संसाधनों के बंटवारे में हम लगातार नाकाम साबित हुए हैं। साथ में यह भी कि गरीबी का सटीक आकलन किए बिना हम नीतियां बनाते रहे हैं। देश में साधन संपन्न और गरीबों के बीच बढ़ती खाई इसका उदाहरण है। हर साल फोर्बस की सूची में हम नए भारतीय अरबपतियों को जुड़ता देख गर्व महसूस करते हैं लेकिन गरीबी के सवाल पर अपने अंदर झांकने की जहमत नहीं उठाते। ■

**कमल संदेश परिवार की ओर से सभी सुधी पाठकों को नव वर्ष 2010 की हार्दिक शुभकामनाएं**